मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 24 अंक : 10

जून 2025

सीज़फायर

क्या मोदी सरकार ने पीओके लेने का मौका गंवा दिया?

भरोसे के लायक नहीं है पाकिस्तान

तिरूपति बालाजी

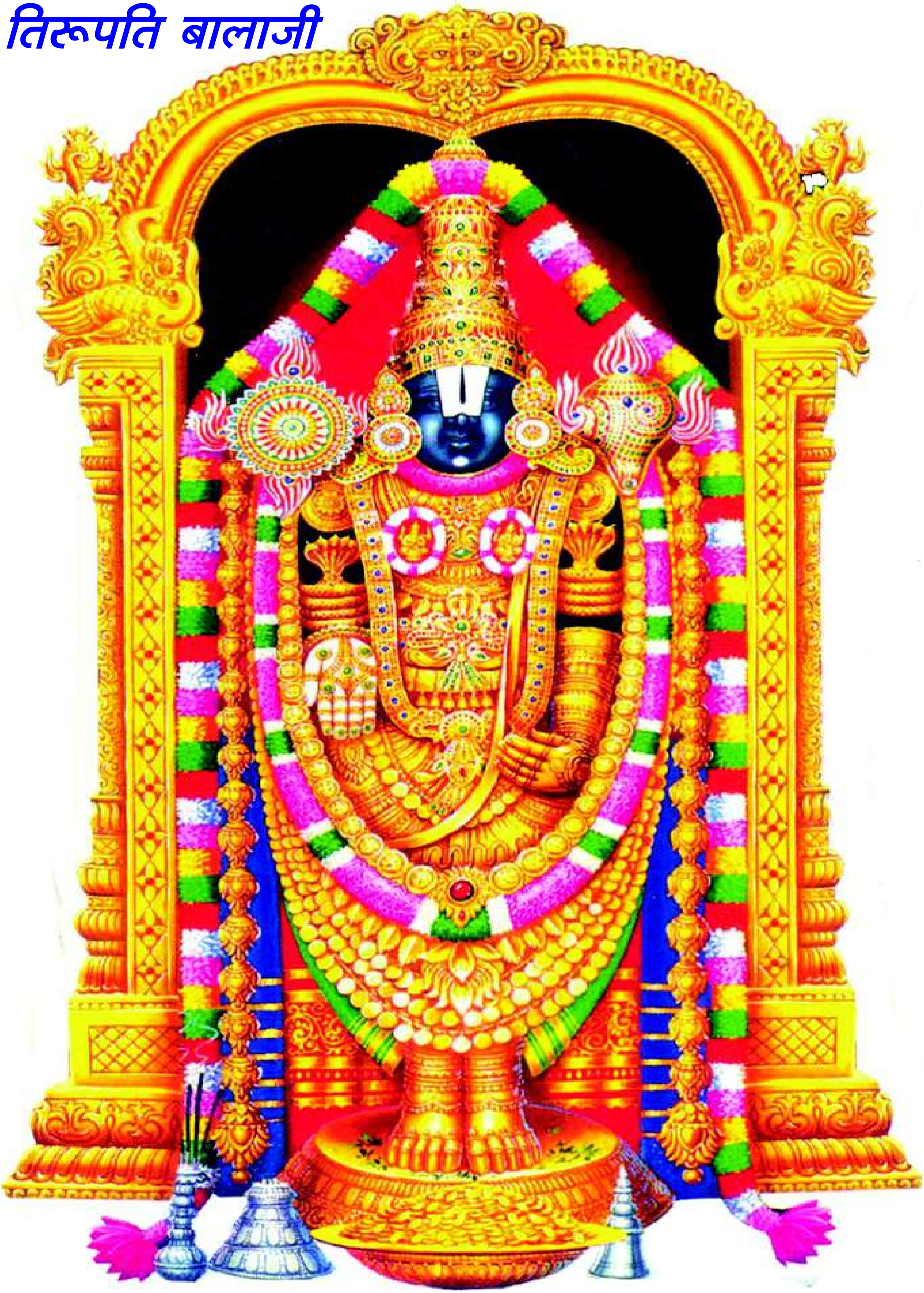

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

(पृष्ठ क्र.-6)

■ अब आजाद है बलूचिस्तान 33

■ युद्ध में सेना जीती, राजनीति हारी 38

■ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाक पर मेहरबान क्यों ? 42

■ कांग्रेस के लिये नासूर बने भूपेश बघेल ! 46

■ Ambedkar's insights and foresight remain deeply underappreciated 61

कोई भी हमारा बालबांका नहीं कर सकता,

क्या यही है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा?

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा ने देश के गौरव के साथ अखण्डता और एकता पर वार किया है। उन्होंने ना सिर्फबीजेपी को बल्कि भारतीय फौज को भी अपमानित किया है। इसके साथ ही यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भारतीय संस्कृति को मिट्टी में मिलाने वाले मध्य प्रदेश के मंत्रियों पर कार्रवाई कर देश के सामने एक मिसाल पेश करे। इनके साथ किसी प्रकार की हमदर्दी दिखाकर बीजेपी अपने आप को कठघरे में खड़ा कर रही है। क्योंकि आज बीजेपी भले ही राष्ट्रीयता की बात करते हुए नहीं थक रही हो लेकिन ऐसे मंत्रियों के साथ नरमी पेश करके खुद पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने की कोशिश करने वाले प्रदेश के मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा की कर्नल सौफिया कुरैशी और सेना पर की गई अभद्र टिप्पणी ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। शाह के इस बयान ने न सिर्फसमाज के महिला वर्ग की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है बल्कि उन्होंने देश की सीमा पर तैनात रहने वाली उन लाखों महिलाओं और बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की है। विजय शाह की इस टिप्पणी ने जहां भारतीय जनता पार्टी की महिला सम्मान की संस्कृति को तार-तार कर दिया है बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिला सैनिकों के सम्मान और वीरता के लिए दिये गये उस सलाम को भी मिट्टी में मिला दिया है जो उन्होंने दो दिन पहले राष्ट्र के संबोधन के नाम पर दी थी। समझने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचारी और दुराचारी मंत्री विजय शाह के दिमाग में गंदगी के अलावा क्या कुछ नहीं है। यह पहला अवसर नहीं है जब शाह ने इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया हो इससे पहले भी विजय शाह झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए फालतू के बयान देते रहे हैं।

देश की बेटियों और सेना पर इस तरह के अभद्र किस्म की टिप्पणी करने वाले यह मंत्रियों को मोहन सरकार को तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए। कुल मिलाकर डॉ. मोहन यादव से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक हर किसी को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और विजय शाह की राजनीतिक यात्रा पर तत्काल प्रभाव से ब्रेक लगाना चाहिए। क्योंकि यह समय डेमेज कंट्रोल का नहीं है बल्कि यह समय फैसला लेने का है अगर भाजपा, सत्ता और संगठन शाह के खिलाफकोई बड़ी कार्रवाई करते हैं तो निश्चित ही यह फैसला अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए एक बड़ा सबक होगा। क्योंकि जो नेता मां-बेटियों और बहनों की इज्जत नहीं करता उसे इस देश और प्रदेश में सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

विजया पाठक

सीज़फायर

क्या मोदी सरकार ने पीओके लेने का मौका गंवा दिया?

भरोसे के लायक नहीं हैं पाकिस्तान

पहलगाम एपिसोड अब खत्म हो गया है। आतंकी हमले से प्रारंभ हुए इस एपिसोड अंततः सीजफायर पर आकर बंद हो गया। लगभग एक पखवाड़े में काफी उथल-पुथल देखने को मिली। कई तरह के कयास भी लगाये गये। कुछ लोगों ने आपदा को अवसर के रूप में देखा क्योंकि उनका मानना था कि इस अवसर पर भारत पीओके को हासिल कर सकता था। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान पोषित आतंकवाद ने भारत की धरती पर जो जुर्रत की है वह माफी के लायक नहीं थी। आतंकी घटना के बाद भारत ने जो एक्शन किया वह सराहनीय है। लेकिन अंत में सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार ने पीओके हासिल करने का मौका गंवा दिया है? क्या ऐसा अवसर भारत को दोबारा मिलेगा? विपक्ष के नेता भी मान रहे हैं कि भारत युद्ध विराम के पहले बड़ा कदम उठना चाहिए था। खासकर पीओके (जहां से ही आतंकवादियों को तैयार किया जाता है) पर अधिकार कर लेना चाहिए था। युद्ध इंदिरा गांधी के समय भी हुआ था लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाकर ही सीजफायर किया था। पाक के दो टुकड़े कर दिये थे। बहरहाल भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का एलान हो गया है। दोनों ही देशों ने गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जता दी है। पूर्व सैनिकों सहित कई लोगों ने संघर्ष विराम को अच्छा निर्णय बताया है लेकिन आगाह भी किया है कि पाकिस्तान कभी भी भरोसे लायक नहीं रहा है। हर बार पाकिस्तान ने धोखा दिया है और आतंकवाद को पनाह दी है। आतंकवाद और शांति वार्ता साथ-साथ नहीं चल सकती है। पाकिस्तान को आतंकवाद और शांति वार्ता में से किसी एक को चुनना होगा। यह पाकिस्तान पर निर्भर करेगा कि वह सीज फायर की स्थिति को बनाए रखेगा कि नहीं। पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे लेने की शर्त को भी जोड़ा जाना चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर में ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अपनी शर्तो पर सीज फायर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली करने की शर्त भी इसमें शामिल होनी चाहिए। अधिकतर आतंकवादी गतिविधियां यहीं से बढ़ती हैं। इतिहास गवाह है कि जब-जब भारत ने पाकिस्तान पर भरोसा किया है, उसने भरोसे को केवल तोड़ा है। 1948, 1965, 1971 और 1999 के युद्ध इसके प्रमाण हैं। पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पोषित करने वाले देश घोषित हो चुका है। पाकिस्तान किसी भी भरोसे या विश्वास लायक देश नहीं है। पहलगाम की आतंकी घटना के बाद विपक्ष ने अपना पूर्ण समर्थन देश की फौज और देश की सरकार को दिया। आज भारत समेत सारी दुनिया इस बात से स्तब्ध है कि अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की?, अमेरिका बीच में कैसे आया? अमेरिका ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक जैसा कैसे तौल दिया। पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को संरक्षण देता है जबकि हिंदुस्तान आतंकवाद से जूझ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में दोनों देश दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाएंगा। ये बीच में व्यापार कहां से आ गया? कूटनीतिक बातों को लेकर देश की जनता के मन में आज कई प्रश्न हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो आतंकवाद पर वार का था व्यापार का नहीं। कश्मीर पर किसी तीसरे देश से बातचीत का कोई स्थान नहीं है। पाकिस्तान को आईएमएफ के जरिए 01 अरब डॉलर का कर्ज मिला जिसमें अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पाकिस्तान को किस बात का इनाम दिया जा रहा है। ट्रंप के बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता।

विजया पाठक

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा था। आतंकियों ने जिस तरह अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने गए लोगों को निशाना बनाया, गोलियों से भून डाला, उससे पूरे देश में उबाल था। लोग आतंकियों के खिलाफ पहले से भी बड़े और निर्णायक एक्शन की मांग कर रहे थे। इंदिरा गांधी की तरह एक्शन लेना पड़ेगा। जिनके एक्शन लेने पर बांग्लादेश को बनाकर पाकिस्तान को दो हिस्सों में तब्दील कर दिया गया था। पता चले उनको भी आतंकवाद पर करारी चोट कैसे होती है। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लीपापोती से काम नहीं चलेगा अब तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। 1967 में जब चीन ने हमारे देश पर हमला किया तो इंदिरा ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो इंदिरा ने मुंहतोड़ जवाब देकर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा को दुर्गा कहा था। पाकिस्तान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाकर आगे की रणनीति पर काम किया। इस हमले के बाद पूरे देश में काफी गुस्सा था। और सरकार पर दवाब बनाया जा रहा था कि वह कोई बड़ा कदम उठाये और इसका मुंहतोड़ जवाब दे। शायद यही कारण था कि हमले के दिन से ही सरकार ने कड़ा रूख अख्तियार किया। देश में तो इस हमले की निंदा हो रही थी वहीं विश्व के अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह

1967 में जब चीन ने हमारे देश पर हमला किया तो इंदिरा ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान ने देश पर हमला किया तो इंदिरा ने मुंहतोड़ जवाब देकर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा को दुर्गा कहा था। पाकिस्तान पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाकर आगे की रणनीति पर काम किया। इस हमले के बाद पूरे देश में काफी गुस्सा था। और सरकार पर दवाब बनाया जा रहा था कि वह कोई बड़ा कदम उठाये और इसका मुंहतोड़ जवाब दे।

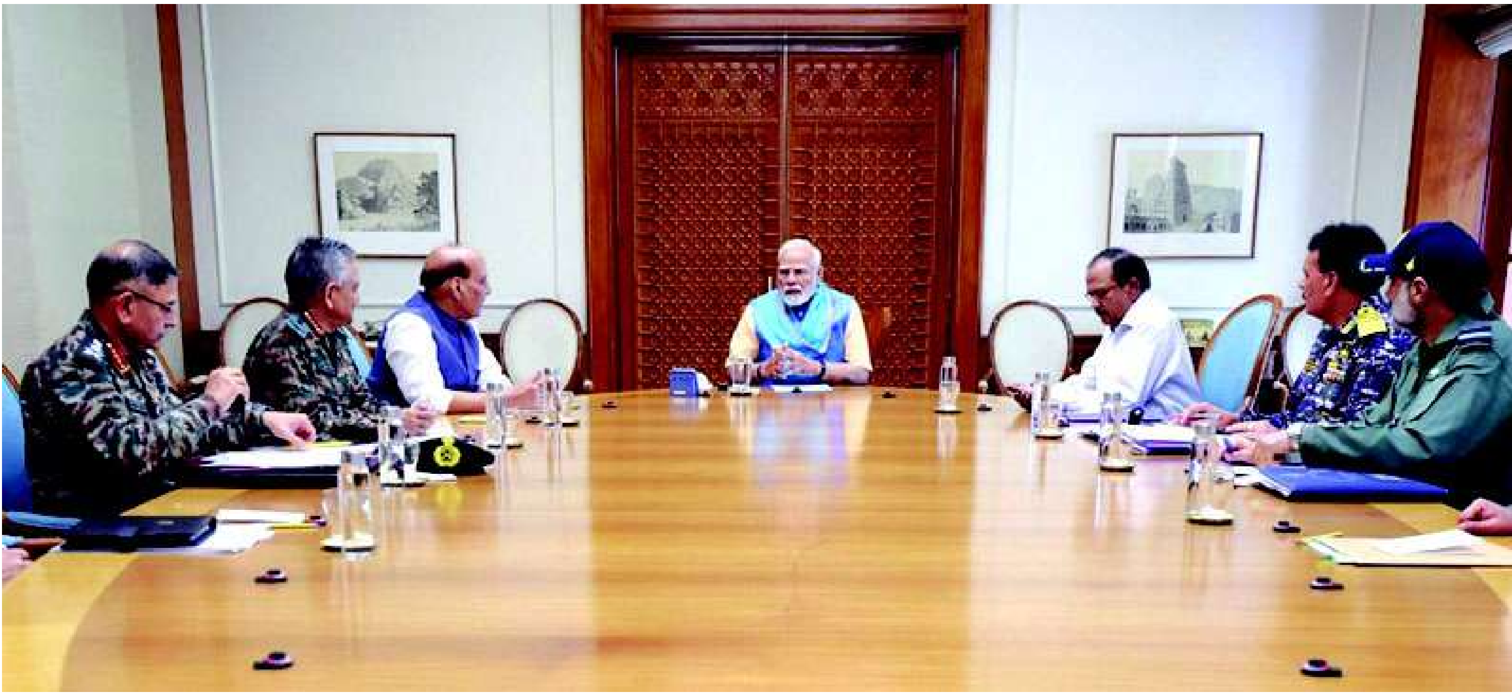

भरोसा दिलाया कि वे इस हमले से उपजी परिस्थितियों में भारत सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम में उसके साथ है। जिस तरह उच्च स्तरीय बैठकों का लंबा दौर चलने के बाद कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे पाकिस्तान घबरा उठा है परन्तु अभी भी वहां के हुक्मरान बड़ी बेशर्मी के साथ ये बयान दे रहे थे कि पहलगाम के आतंकी हमले में उनके देश का कोई हाथ नहीं है जबकि प्रारम्भिक जानकारी के अनुसार पहलगाम

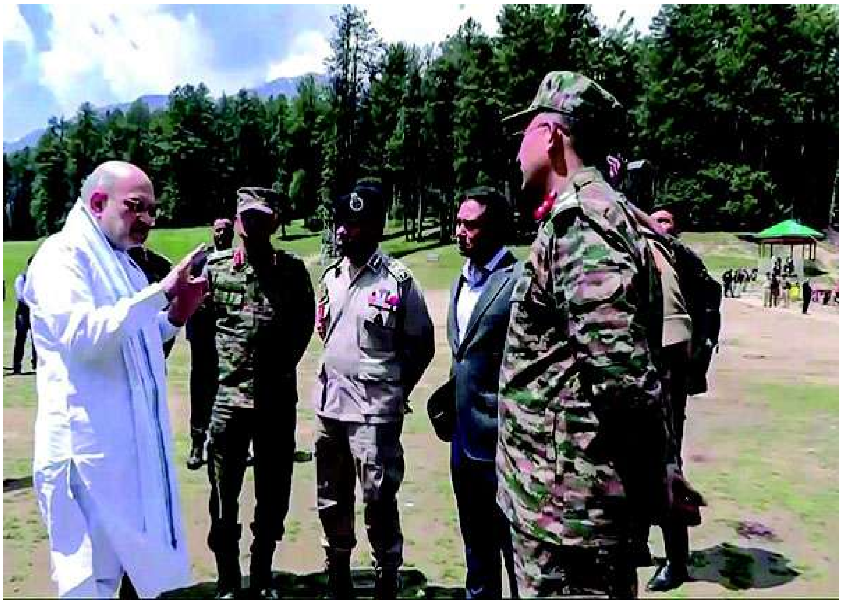

के आतंकवादियों को पाकिस्तान से निर्देश दिए जा रहे थे। आतंकवाद की इस वीभत्स वारदात के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति का भले ही अभी खुलासा नहीं हुआ था लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह बयान कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सरकार के मजबूत इरादों की अभिव्यक्ति कर रहा था। पाकिस्तान को कठोरतम सबक सिखाने की मंशा से केंद्र सरकार जो भी कारवाई करेगी उसमें सारा देश उसके साथ था। निकट भविष्य में ही पाकिस्तान के विरूद्ध किसी बहुत बड़ी कार्रवाई की सारा देश व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा था। यह भी पहली बार हुआ कि आतंकियों ने पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। इसका मतलब साफ है कि जम्मू-कश्मीर में पर्यटन उद्योग को तहस नहस करने के इरादे से यह हमला किया गया इसीलिए आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की ऐसी निर्ममता के साथ हत्या कर दी। पहलगाम हमले के बाद भारत और

पाकिस्तान में काफी उथल पुथल देखने को मिली। दोनों देशों में काफी हलचल थी। सवाल यह भी था कि आखिर इसी समय पहलगाम हमले को अंजाम क्यों दिया गया, जिसे पुलवामा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है? इसके कई कारण हैं। एक तो मुंबई हमले के षड्यंत्रकारी तहव्वुर राणा को भारत लाये जाने के बाद से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं कि पता नहीं, वह इस्लामाबाद के कौन-से रहस्य पर से पर्दा उठा दे। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला भीषण तो है ही, साथ ही साथ कायराना भी है। जब कश्मीर घाटी आतंकवाद से त्रस्त थी और आये दिन आतंकी हमले होते थे, तब भी पर्यटकों को निशाना बनाने से यथासंभव बचा जाता था, क्योंकि पर्यटक जम्मू-कश्मीर की जीवनरेखा हैं। पर्यटकों से ही वहां के स्थानीय लोगों का गुजारा चलता है।

यह पहले से ही पता है कि आतंकवाद को जिलाये रखने के लिए पाकिस्तान में टीआरएफ जैसे छोटे-छोटे कई आतंकवादी संगठन बने हुए हैं। ये संगठन जम्मू-कश्मीर में लोन वुल्फ अटैक जैसे छोटे हमले भी करते रहे हैं, ताकि आतंकवाद को जीवित रखा जा सके। ऐसे ही एक गुट ने इस हमले को अंजाम दिया। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाने का ठीक वह समय चुना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सउदी अरब की दो

दिवसीय यात्रा पर निकले हुए थे। प्रधानमंत्री का यह दौरा व्यापार, पर्यटन, उर्जा और सैन्य संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। वास्तविकता यह है कि भारत और सउदी अरब ने पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक सहयोग, रक्षा सहयोग, उर्जा साझेदारी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से आपसी संबंधों को मजबूत किया है। और यह भी देखने लायक है कि सउदी अरब से भारत की यह दोस्ती पाकिस्तान की कीमत पर परवान चढ़ी है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने पर पाकिस्तान ने तब अपने परम मित्र सउदी अरब को अपने साथ लेना चाहा था। लेकिन सउदी अरब ने न केवल तटस्थ रास्ता चुना, बल्कि तब से पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते भी पहले वाले नहीं रह गये। इस्लामाबाद को इस बात की नाराजगी है कि उसका दोस्त सउदी अरब अब भारत के साथ है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की सउदी अरब यात्रा के दौरान पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले का एक और महत्वपूर्ण कारण अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का इस समय भारत में होना है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार से दुनिया भर में खलबली मची है और ट्रंप के मुख्य निशाने पर पाकिस्तान का दोस्त चीन है। लेकिन पाकिस्तान यह भी देख रहा है कि उसी अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के चार दिनों के दौरे पर आये हैं, उनकी प्रधानमंत्री मोदी से कई मुद्दों पर सफल बातचीत हुई है, वह भारतीय प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। इस बीच मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता लाने के लिए लगातार प्रयास किये हैं। घाटी में पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विभिन्न मोर्चों पर भारत की इतनी सफलता पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही। इसलिए पहलगाम में आतंकी हमलों को अंजाम देकर उसने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को प्रकारांतर से यह

सीजफायर पर उठते सवाल

भारतीय सेना पहलगाम में हुए हमले का बदला लेने के लिए आतंकवादियों और उनके समर्थकों को मुंहतोड़ जबाव दे रही थी, तब क्या कारण थे कि अमेरिका ने एकदम से सामने आकर भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। पहलगाम हमले का बदला पूरा होने से पहले ही सीजफायर क्यों हुआ? सीजफायर कैसे हुआ? क्या हमें देश की बहन-बेटियों के सिंदूर का बदला मिल गया? क्या पहलगाम के आतंकी भारत को सौंपे गए? आज पूरा देश जानना चाहता है कि अगर पाकिस्तान ने खुद हाथ जोड़कर सीजफायर की मांग की तो इसकी घोषणा भारत के बजाए अमेरिका ने क्यों की? क्यों पाकिस्तान दुनिया के सामने आकर नहीं बोलता की हमने हार मानी? क्यों कोई समझौता नहीं हुआ? क्यों पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला करने वाले आतंवादियों को अब तक भारत को नहीं सौंपा? पीएम मोदी से आज पूरा देश जानना चाहता है, क्या व्यापार बंद होने की धमकी की वजह से आपने सीजफायर किया? क्या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत की बहन-बेटियों के सिंदूर से भी ज्यादा कीमती हो गया है? 22 अप्रैल को पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ। आतंवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर हमला किया। पूरे देश ने हमारी बहन-बेटियों के आंसू देखे। देश चाहता था कि हमारी उन बहन-बेटियों के सिंदूर का बदला लिया जाए। 07 मई को जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तब पूरा देश भारतीय सेना के साथ एकजुट होकर खड़ा था और भारतीय सशस्त्र बलों ने अपना लोहा मनवाते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इस समय एक-एक राजनीतिक पार्टी सरकार के साथ

खड़ी रही क्योंकि ये हमारे देश की बात थी। लेकिन 10 मई को अचानक से युद्ध विराम की घोषणा हो गई। ये घोषणा भारत या भारत की सेना नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने की। ये सीजफायर कैसे हुआ? क्या हमें देश की बहन-बेटियों के सिंदूर का बदला मिल गया? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प के दबाव में

बताने की कोशिश की है कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति गंभीर है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में घाटी में किये जाने वाले आतंकी हमले की गंभीरता वैसे ही बढ़ जाती है। इस संदर्भ में यह याद किया जाना चाहिए कि 2000 में भी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भारत दौरे से पहले जम्मू-कश्मीर के छत्तीसिंहपुरा में सुनियोजित ढंग से आतंकी हमला किया गया था।

सीजफायर क्यों किया? क्या ट्रम्प ने व्यापार बंद करने की धमकी देकर सीजफायर के लिए मजबूर किया? पहलगाम में आतंकवादियों को मौत के घाट क्यों नहीं उतारा गया? जब भारत पीओके पर कब्जा व बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर सकता था, तो फिर प्रधानमंत्री सीजफायर के लिए क्यों तैयार हुए? नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया है, तो फिर तीन घंटे बाद ही उसने सीजफायर का उल्लंघन क्यों किया?

युद्धविराम की आलोचनाः कुछ लोगों ने इस युद्ध विराम की आलोचना भी की है। क्या इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को पूरा नहीं करने का फैसला किया है? क्या वे पाकिस्तानी सेना के जनरलों की 'हजार घावों की रणनीति' को हमेशा के लिए खत्म नहीं करेंगे, जिसमें वे आतंकवादियों के जरिए भारत पर हमला करते हैं? जीत के मुंह से हार छीनना भारत की पुरानी राजनीतिक परंपरा रही है। भारत ने 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्धविराम किया था, जबकि सेना जीत की ओर बढ़ रही थी। फिर, 1972 में शिमला में, भारत ने 1971 के युद्ध में मिली जीत को बिना कुछ लिए ही पाकिस्तान को दे दिया। भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था। पाकिस्तान आतंकवादियों का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। भारत को इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए था। भारत पहले भी कई बार ऐसे मौके गंवा चुका है।

क्या भारत ने सही फैसला लिया?: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसले लिए हैं, उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है कि सिंधु नदी के पानी को लेकर जो समझौता है, उस पर भी दोबारा विचार किया जा सकता है। भारत हमेशा से कहता रहा

है कि वह पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी करेगा, जब पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर देगा। पाकिस्तान की वजह से दोनों देशों के बीच पिछले दस सालों से कोई बातचीत नहीं हुई है। इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या भारत ने सही फैसला लिया? क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या यह युद्ध विराम स्थायी होगा? इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं।

लेकिन पाकिस्तान की मंशा के विपरीत, विश्व समुदाय ने पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किये गये आतंकवादी हमले की निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और हमले के दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को पूर्ण समर्थन देने की बात कही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इस हमले पर एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त

भारत-पाकिस्तान में पहला सीजफायर कब हुआ था

जब दो देशों के बीच युद्ध की परिस्थिति होती है, तब दोनों के बीच एक समझौता किया जाता है। इसका सीधा अर्थ होता है कि अब हम एक-दूसरे पर किसी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे। जल, थल और वायुसेना किसी भी तरह से कोई हमला नहीं किया जाएगा। सीजफायर का सीधा अर्थ है कि तत्काल प्रभाव से तनाव को कम करके शांति की ओर बढ़ना। इसके जरिए दोनों देश वादा करते हैं कि सीमा पर किसी भी तरह की कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके लिए किसी औपचारिक संधि की कोई जरूरत नहीं होती है। सीजफायर के बावजूद अगर कोई देश सीमा पर आक्रामक कार्रवाई करता है, तो उसे सीजफायर का उल्लंघन कहा जाता है। भारत-पाकिस्तान के बीच पहला सीजफायर तब हुआ था, जब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में जंग हुई थी। वो साल 1947 था, तब इसी जंग में यूएन ने दोनों देशों के बीच सहमति से सीजफायर करवाया था। 1947 में जब भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, तब पाक ने कश्मीर पर कब्जे की कोशिश की थी। उस वक्त पाकिस्तानी सेना और कबायली लड़ाकों ने जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ कर दी थी। उस वक्तदोनों देशों के बीच पहला सीजफायर हुआ था। तभी LOC की नींव रखी गई थी। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश की थी। तब भारत ने पड़ोसी मुल्क पर हमला किया था। 17 दिन के बाद सोवियत संघ और अमेरिका ने मध्यस्थता की, तब जाकर 23 सितंबर 1965 को दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश को अलग करने के लिए युद्ध चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की हार हुई थी। तब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। ये सीजफायर बांग्लादेश के एक स्वतंत्र देश बनने के साथ खत्म हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की थी। पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि उसने हमेशा सीजफायर का उल्लंघन किया है। इसकी वजह से भारत के कई जवान शहीद भी हो गए।

की हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी आदि ने इस हमले की भारी भर्त्सना की है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय संघ ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की है। जाहिर है, पहले की तरह इस बार भी आतंकी हमले के जरिये भारत को विश्व समुदाय के सामने कमतर या खंडित साबित करने की पाकिस्तान की

साल 2003 में हुए समझौते बावजूद पाकिस्तान ने LOC पर कई बार गोली चलाई 2013, 2016 और 2019 में। उल्लंघन करके यह दिखा है कि उसकी फितरत हमेशा से मुकर जाने की ही रही है। इसके बाद अभी जब 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, तब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाक को कड़ा जवाब दिया। इसके बाद युद्ध जैसे हालात बन गए। इसके बाद अमेरिका ने मध्यस्थता की और 10 मई 2025 को शाम 5 बजे सीजफायर लागू हुआ, लेकिन इसके 2-3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन कर दिया।

हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदम

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक नीतिगण निर्णय लिए। जिसमें सिंधु जल संधि का निलंबन जिसमें 1960 की संधि में निहित भारत के संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने इस संधि को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है, जब तक कि पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद का सार्वजनिक परित्याग नहीं करता। भारत ने दूसरा कदम पाकिस्तान के खिलाफ वीजा रद्द करने का लिया है जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा स्कीम से बाहर निकाल दिया है और 27 अप्रैल से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को जारी भारतीय वीज़ा निरस्त कर दिए गए। पाकिस्तानी नागरिकों को जल्दी से जल्दी भारत छोड़ने की सलाह दी और नए वीज़ा जारी करना तत्काल प्रभाव से

मंशा बेकार साबित हुई। उल्टे पाकिस्तान की तरफ से आये हुए कुछ बयानात उसे ही संदेह के घेरे में डालते हैं। पहलगाम हमले से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने इस्लामाबाद में आयोजित प्रवासी पाकिस्तानियों के एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताते हुए कहा था कि उनके पूर्वज मानते थे, हिंदू और मुसलमान जीवन के हर

स्थगित किया गया। भारत का तीसरे कदम के रूप में अटारी-वाघा सीमा बॉर्डर को बंद करना एवं द्विपक्षीय व्यापार संबंध स्थगित करना।

पहलगाम आतंकी हमले की पूरी कहानी

कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बायसरन में हुए आतंकी हमले 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक थे। यह 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है। ये हमला ऐसे वक्त हुआ, जब पीएम मोदी देश से बाहर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर हैं। ये आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। फरवरी, 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू-कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली। खुफिया एंजेसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टर माइंड लश्कर-ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद था। बताया जा रहा है सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फूलों से स्वागत करती है। वह सेना के अधिकारियों की पूरी मदद करता है। साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। पहलगाम आतंकी हमले से दो महीने पहले सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। यहां उसे पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खट्टक ने जिहादी भाषण देने के लिए वहां बुलाया था। वहां उसने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया। जम्मू-कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों को वही अंजाम दे रहा है। आतंकी हमले में अब तक 06 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हमलावरों में दो पाकिस्तानी और दो स्थानीय आतंकी शामिल थे। दो अन्य के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। कहा जा रहा है कि घटना स्थल पर आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते आए थे। यह माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बायसरन पहुंचे। कुछ लोगों ने आतंकियों की संख्या पांच बताई है।

पहलू में अलग हैं। जनरल मुनीर का वह बयान बेहद ही घटिया और उकसाने वाला था। कुछ खुफिया अधिकारियों का यह मानना है कि जनरल मुनीर के उत्तेजक भाषण ने लश्कर के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को आतंकी हमले के लिए उकसाया। पहलगाम हमले पर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान भी उतना ही निंदनीयथा पहले उन्होंने कहा कि पहलगाम

उरी से पुलवामा तक

मोदी सरकार में हुए ये बड़े हमले

उरी हमलाः 18 सितंबर, 2016 को जम्मू-कश्मीर के उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास स्थित भारतीय सेना के कैम्प पर हमला किया गया था। इस हमले में 19 जवान मारे गए थे। इस हमले को दो दशकों का सबसे बड़ा हमला बताया गया।

पठानकोट हमलाः 02 जनवरी 2016 को चरमपंथियों ने पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। इसमें 07 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे जबकि 20 अन्य घायल हुए थे। जवाबी कार्रवाई में चार चरमपंथियों की भी मौत हुई थी।

गुरदासपुर हमलाः 27 जुलाई 2015 को पंजाब को गुरदासपुर के दीनापुर में हमलावरों ने तड़के ही एक बस पर फ़ायरिंग की और इसके बाद पुलिस थाने पर हमला कर दिया। हमले में एसपी (डिटेक्टिव) समेत चार पुलिसकर्मी और तीन नागरिक मारे गए।

अमरनाथ यात्रियों पर हमलाः 10 जुलाई 2017 को अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं पर अनंतनाग ज़िले में एक चरमपंथी हमला हुआ। इस हमले में 07 लोग मारे गए थे।

पुलवामा हमलाः पुलवामा ज़िले में श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर चरमपंथियों ने आईईडी धमाका कर सीआरपीएफ के काफ़िले पर हमला किया है। इस हमले में 42 जवान शहीद हो गए और कई जख़्मी हुए। इस हमले को उड़ी से भी बड़ा हमला बताया गया।

नगरोटा हमलाः 29 नवंबर 2016 को नगरोटा में सेना की 16वीं कोर पर हमले में सेना के 07 जवान शहीद हो गए थे।

सुंजवान सैन्य कैंप हमलाः जम्मू जिले के सुंजवान सैन्य कैंप पर आतंकियों के हमले में 6 जवान शहीद हो गए थे। घटना 10-11 फरवरी 2018 की है।

हमले से पाकिस्तान का कोई लेना-देना नहीं है। फिर उन्होंने भारत के खिलाफ ही जहर उगला। हमारी सरकार ने इस हमले को अत्यंत गंभीरता से लिया है, जो आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की हमारी नीति के बारे में ही बताता है।

खैर, अब देश में मोदी सरकार है। चौतरफा दवाब के चलते सरकार का एक्शन तो लेना ही था। पहलगाम आतंकी

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2014 के मुकाबले 2018 में 133.63 प्रतिशत ज्यादा आतंकी मारे गए थे। 2014 में 110 आतंकी सेना के ऑपरेशन में मार गिराए गए, जबकि 2018 में 257 आतंकियों को ढेर किया गया। साल 2014 से 2018 के बीच जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवानों की संख्या में 93 फीसदी का इजाफा हुआ है। इसके अलावा इन पांच सालों में जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 176 फीसदी का इजाफा हुआ है। गृह मंत्रालय के मुताबिक साल 2014 के मुताबले साल 2018 में जम्मू-कश्मीर में नागरिकों, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों- तीनों की मौतों में इजाफा हुआ है। 2014 से 2018 के बीच नागरिकों

हमले के कुछ दिन बाद सारी तैयारियां करने के बाद आखिरकार मोदी सरकार ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर पाकिस्तान पर बमबारी कर दी। शुरूआत में भारतीय सीमाओं पर पाकिस्तान की ओर ड्रोन से हमले किये गये। इन ड्रोन को नाकाम करने में भारत की सेना ने सफलता पायी। लगभग एक पूरी रात पाक ने भारतीय सीमा पर ड्रोन से हमले किये। अभी भारत ने केवल इन ड्रोन को नष्ट करने का काम किया। इसके बाद भारत ने भी पाकिस्तान के 100 किमी अंदर तक मिसाइलें दागकर उनके एयरबेज और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन के अंदर ही भारत ने इसका बदला ले लिया है। भारतीय

भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसमें करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है।

की मौत में 35.71 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। जबकि आतंकी हमलों में शहीद होने वाले सुरक्षाबलों की संख्या में 93 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साल 2014 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में 47 जवानों ने जान गंवाई थी। जबकि साल 2018 में 91 जवान शहीद हुए। इस तरह 2014 के मुकाबले 2018 में 44 जवान ज्यादा शहीद हुए। हालांकि, 2014 के मुकाबले 2018 में 133.63 प्रतिशत ज्यादा आतंकी मारे गए थे। 2014 में 110 आतंकी सेना के ऑपरेशन में मार गिराए गए, जबकि 2018 में 257 आतंकियों को ढेर किया गया। 2014 से 2018 के बीच जम्मू-कश्मीर में कुल 1315 लोग आतंकवाद की वजह से मारे गए। इसमें 138 (10.49 प्रतिशत) नागरिक थे, 339 (25 प्रतिशत) सुरक्षा बल और 838 (63.72 प्रतिशत) आतंकी थे। 2014 से 2018 के बीच जम्मू-कश्मीर में कुल 1708 आतंकी हमले हुए। कहा जा सकता है कि इस हिसाब से हर महीने 28 आतंकी हमले जम्मू-कश्मीर में हुए। इन आंकड़ों को लोकसभा में जारी किया था। 2014 से 2018 के बीच जम्मू-कश्मीर में कुल 1315 लोग आतंकवाद की वजह से मारे गए। इसमें 138 (10.49 प्रतिशत) नागरिक थे, 339 (25 प्रतिशत) सुरक्षा बल और 838 (63.72 प्रतिशत) आतंकी थे। 2014 से 2018 के बीच जम्मू-कश्मीर में कुल 1708 आतंकी हमले हुए। 2014 में राज्य में 222 आतंकी घटनाएं हुई थी। 2015 में इसमें मामूली कमी आई और ये आंकड़ा 208 हो गया। लेकिन 2016 के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में लगातार इजाफा हुआ है। 2016 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में 54.8 का इजाफा हुआ, 2017 में 6 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया। इस साल 342 आतंकी हमले हुए। 2018 में इस आंकड़े में 79.53 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया। 2018 में 614 आतंकी हमले हुए। आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में हर महीने 51 आतंकी हमले हुए।

ऑपरेशन सिंदूर से निस्तनामूद हुए पाक के मंसूबे भारत के पराक्रम से पस्त हुआ पाक

सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसमें करीब 100 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हमले के बाद भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया था, इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जिन लक्ष्यों को चुना उनमें से चार पाकिस्तान में और पांच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हैं। भारतीय सेना की कार्यवाही से पाकिस्तान सकते में आ

गया। अब उसे अपने देश को बचाने के लिए हाथ पैर मारना था। पाकिस्तान के अंदर भी एक युद्ध जैसा माहौल बन गया था। बलूस्तिान के विद्रोहियों ने पाक के सैन्य ठिकानों को नष्ट करना शुरू कर दिया। आनन-फानन में पाकिस्तान अब किसी भी तरह सीजफायर की बात करने लगा। उसने कई देशों से गुहार लगाई कि

गंवाया मौका : ऑपरेशन सिंदूर से हासिल किया जा सकता था पीओके

यह युद्ध रूकवा दीजिए। भारत ने इसी तरह का हमला फरवरी 2019 में उस समय किया था, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के एक काफिले को निशाना बनाया गया था। इस हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बालाकोट में हमला कर आतंक के ठिकानों को तबाह कर दिया

आतंकवाद विरोधी अभियानों में मारे गए 172 आतंकवादी

जम्मू-कश्मीर पुलिस की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों में मारे गए 172 आतंकवादियों में से 108 टीआरएफ से जुड़े थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न आतंकी संगठनों द्वारा भर्ती किए गए 100 व्यक्तियों में से, टीआरएफ 74 की भर्ती के लिए जिम्मेदार था। जनवरी 2024 में, टीआरएफ ने अपनी 'वार्षिक रिपोर्ट 2023' प्रकाशित की, जिसमें जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 68 हमलों की जिम्मेदारी ली गई। इस विवरण में जम्मू-कश्मीर में 64 घटनाएं दिखाई गई हैं- दक्षिण कश्मीर में 26, उत्तरी कश्मीर में 7, मध्य कश्मीर में 24 और जम्मू में 7 - साथ ही लद्दाख में तीन और दिल्ली में एक हमला हुआ। 05 जनवरी 2023 को इसके गठन के लगभग तीन साल बाद गृह मंत्रालय (एमएचए) ने टीआरएफ को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (पी) एट, 1967 के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया। प्रतिरोध मोर्चा वर्ष 2019 में लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया, जो यूएपीए के तहत पहली अनुसूची के सीरियल नंबर 5 पर सूचीबद्ध एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। समूह का उदय वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की जांच से बचने के लिए लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) जैसे अति धार्मिक संगठनों से खुद को दूर करके पाकिस्तान की रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। टीआरएफ का नाम, इस्लामी अर्थों से रहित, वैश्विक रूप से प्रतिरोध आंदोलन के रूप में प्रतिध्वनित करने के लिए चुना गया था।

था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था, ऑपरेशन बंदर। कार्रवाई को पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई बताया। उसका कहना है कि उसके पास जवाबी कार्रवाई का हक है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान पर एयरस्ट्राइक कर कई सैन्य और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान

पाकिस्तान ने हर युद्ध में मुंह की खाई

वैसे तो पाकिस्तान की करतूतों ने कई बार जंग जैसे हालात पैदा किए हैं, लेकिन भारत ने हमेशा से शांति ही चाही। इसके बाद भी स्थितियां ऐसी बनी कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के नौ ठिकानों पर बमबारी की। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए 5-6 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 09 ठिकानों पर बमबारी की। पहलगाम अटैक से पूरा देश दहल गया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने जहां हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। अब तक इंडिया और पाकिस्तान की बीच चार बार युद्ध हुए हैं-

भारत-पाकिस्तान युद्ध 1947-48- भारत और पाकिस्तान के बीच पहली लड़ाई 22 अक्टूबर 1947 को हुई थी। दरअसल, सभी प्रिंसली स्टेट्स को तीन ऑप्शन दिए गए थे पहला कि वो इंडिया को अपना देश चुन लें, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा था कि वे स्वतंत्र राज करे। अब जम्मू-कश्मीर के राजा दोनों देशों में से किसी में भी शामिल न होकर स्वतंत्र राज करना चाहते थे। हालांकि, भारी दबाव के कारण जम्मू और कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, जिसका मतलब था कि जम्मू और कश्मीर

को सबक सिखाने के विषय पर विपक्ष भी खुलकर सामने आई और केंद्र की मोदी सरकार के समर्थन में दिखी। ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्र के नाम अपने पहले संदेश में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी इसे अस्थायी तौर पर रोका गया है। अब भारतीय सेना ने पीएम मोदी के संदेश में छिपी उस चेतावनी को जगजाहिर कर दी

भारत का हिस्सा होगा। इससे पाकिस्तान का खून खौल गया और इसी बौखलाहट में उसे कश्मीर में अपनी सेना भेज दी, जिससे जंग का आगाज हुआ। पाकिस्तानी ट्राइबल सेनाओं ने कश्मीर पर हमला करके कई शहरों पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना जंग के मैदान में उतरी और क्षेत्र पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ाई लड़ी।

भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965- बंटवारे के बाद से कश्मीर की स्थिति अनसुलझी रही है। ऐसे में इस लड़ाई की असल वजह भी जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र पर विवाद होना था। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस इलाके पर अपना दावा किया, जिससे बॉर्डर पर हुई झड़पों के बाद तनाव ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान ने स्थानीय विद्रोहियों का समर्थन किया, जिसके बाद यह झड़पें जंग में तब्दील हो गईं। लगभग 05 हफ्ते तक चली इस लड़ाई में आखिरकार भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल दिया और युद्ध ताशकंद समझौते के तहत यूएन द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद सीजफायर लाइन बनी, जो बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, लेकिन कश्मीर विवाद अनसुलझा रहा।

भारत-पाकिस्तान युद्ध 1971- साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में दुनिया ने एक बार फिर भारत की सैन्य ताकत देखी। यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक और जातीय तनाव के कारण हुआ था। इसी जंग की बदौलत बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पश्चिमी क्षेत्र में लोंगेवाला की लड़ाई एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जहां भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ कर रख दिया था। इस संघर्ष के बाद कई सालों तक भारत-पाकिस्तान के संबंध खराब रहे।

भारत-पाकिस्तान युद्ध 1999- भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 तक जम्मू और कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में युद्ध लड़ा गया, जो कारगिल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। यह जंग तब शुरू हुई, जब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने भारत-नियंत्रित कारगिल में प्रवेश किया और एलओसी के साथ अहम रणनीतिक पॉइंट्स पर कब्ज़ा कर लिया। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी हमला किया और घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। जुलाई 1999 में युद्ध विराम के बाद लड़ाई तो बंद हो गई, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच तनाव जारी रहा।

है, जो पाकिस्तानी फौज और उनके आकाओं की नींदें उड़ा सकती है। भारतीय सेना ने साफ शब्दों में बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर का विकराल रूप अभी बाकी है। सेना की ओर से इस चेतावनी के पीछे उसकी पूरी रणनीति और भारत की वैश्विक स्थिति शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान और उसकी फौज दूर-दूर तक कहीं खड़ा नहीं है।

जम्मू-कश्मीर में 2000 के बाद हुए आंतकी हमले

- **अनंतनाग जिले में अल्पसंख्यक सिखों पर हमला-** ये आतंकी हमला 21 मार्च 2000 की रात को अनंतनाग जिले के छत्तीसिंहपोरा गांव में किया गया था। इस हमले में आतंकियों ने अल्पसंख्यक सिख समुदाय को निशाना बनाया गया था। इस आतंकी हमले में कुल 36 लोगों की जान गई थी। जबकि कई लोग घायल भी बताए गए थे।
- **पहलगाम के नुनवास बेस पर आतंकी हमला-** 2000 के अगस्त पहलगाम के नुनवान बेस कैंप हुए आतंकी हमले में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों को निशाना बनाया गया। इस हमले में स्थानीय लोगों के साथ-साथ कुल 32 तीर्थ यात्रियों की हत्या की गई थी।
- **अमरनाथ यात्रियों पर हमला-** जुलाई 2001 में अमरनाथ यात्रियों को आतंकियों ने निशाना बनाया। इस हमले में आतंकियों ने 13 लोगों की हत्या की थी। ये हमला अनंतनाग के शेषनाग बेस कैंप पर हुआ था।
- **विधानमंडल परिसर पर हुआ था फिदायीन हमला-** जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में राज्य विधानमंडल परिसर पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में उस दौरान 36 लोग मारे गए थे जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
- **चंदनवारी कैंप में हमला-** 2002 में कश्मीर के चंदनवारी बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 11 अमरनाथ यात्री मारे गए थे।
- **दक्षिण कश्मीर में हुआ था बड़ा हमला-** ये हमला 23 नवंबर 2002 को जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे पर हुआ था। हम इस हमले में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से विस्फोट किया गया था। इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी, तीन महिलाएं और दो बच्चों समेत 19 लोगों की जान चली गई थी।

हालांकि सीजफायर को लेकर मोदी सरकार की आलोचना हुई और आरोप लगाया कि सरकार ने अखंड भारत के सपने को साकार करने का मौका गंवा दिया गया। अगर यह सैन्य कार्रवाई चार दिन और जारी रहती तो भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर कब्जा कर लेती। सैन्य कार्रवाई रोकने से पहले भारत को कम से

● **23 मार्च 2003 को हुआ हमला-** इस हमले में आतंकवादियों ने पुलवामा जिले के नंदी मार्ग गांव में 11 महिलाओं और 02 बच्चों सहित कम से कम 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी।

● **13 जून 2005-** पुलवामा को एक बार फिर आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। यह हमला एक सरकारी स्कूल के सामने भीड़भाड़ वाले बाजार में विस्फोटकों से लदी कार से विस्फोट किया था। इस हमले में 02 स्कूली बच्चों समेत कुल 13 लोग मारे गए थे।

● **12 जून 2006-** आतंकियों ने इस बार कश्मीर के कुलगाम को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में 9 नेपाली नागरिक और बिहारी मजदूर मारे गए थे।

● **उरी हमला 18 सितम्बर 2016-** जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हुआ, एक आतंकी हमला था जिसमें 16 जवान शहीद हो गए थे। सैन्यबलों की कार्यवाही में सभी चार आतंकी मारे गए। यह भारतीय सेना पर किया गया, लगभग 20 सालों में सबसे बड़ा हमला था। आतंकी आकाओं ने बेहद गहरी साजिश के साथ हमला किया था। उन्होंने वक्तचुना था जब उरी कैंप से 10 डोगरा के जवान अपना कार्यकाल पूरा करके दूसरे मोर्चे पर जाने की तैयारी कर रहे थे और उनकी जगह 06 बिहार रेजीमेंट के जवान आ चुके थे। इस अदला-बदली के वक्तको ही हमले के लिए चुना गया था। इस हमले के महज 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था। इस ऑपरेशन में 150 कमांडोज की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। भारतीय जवानों ने 28-29 सितंबर की दरम्यानी रात को पीओके में सीमा के भीतर तीन किलोमीटर अंदर तक घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर डाला। इसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे।

● **10 जुलाई 2017-** कश्मीर के कुलगाम में अमरनाथ यात्रा के लिए जा रही बस पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 08 लोगों की मौत हो गई थी।

● **22 अप्रैल 2025-** पहलगाम के बैसारन घाटी में आतंकियों ने टूरस्टों को अपना निशाना बनाया। इस हमले 26 पर्यटकों के मारे गए हैं।

कम पीओके को वापस लेना चाहिए था और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देना चाहिए था। चार दिनों तक सीमा पार से ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद दोनों देश पूर्ण स्तर के युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट से सबको हैरान किया। इसमें उन्होंने दावा किया था कि दोनों पक्षों के बीच अमेरिका ने

मनमोहन के 10 साल और मोदी के 11 साल

मनमोहन के कार्यकाल में 4241 और मोदी के समय 701 आतंकी मारे गए। मनमोहन के 10 साल के कार्यकाल में 4241 आतंकी मारे गए थे, जबकि मोदी के 4.5 साल में 701 आतंकी मारे गए थे। 2004 से मई 2014 तक यूपीए की सरकार थी जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। खबर के मुताबिक 2004 से 2013 तक 1788 आम लोग, 1177 जवान और 4241 आतंकी मारे गए थे। हालांकि, यूपीए-1 (2004-2009 तक) में ही 3,424 आतंकी सेना ने मार दिए थे। जबकि, मोदी मई 2014 से प्रधानमंत्री हैं और 17 जून 2018 तक के आंकड़े उस वक्त मौजूद थे। मई 2014 से जून 2018 तक 161 आम लोग और 701 आतंकी मारे गए थे। वहीं, इस बीच 303 जवान भी शहीद हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के सिर्फ 06 साल के कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा 10,147 आतंकी मारे गए थे। अटल सरकार (मार्च 1998-मई 2004 तक) में 5,082 आम नागरिक मारे गए और 2,929 जवान शहीद हुए थे।

मध्यस्थता की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने भारत-पाक संघर्ष के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में सीजफायर किया। ऐसा करने की जरूरत नहीं थी और हमने ऐसा करके पीओके को वापस हासिल करने का सुनहरा अवसर गंवा दिया।

आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच बीते भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की ओर से सीजफायर किया गया था। दोनों देशों के बीच आपसी सहमति बनी, लेकिन सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर सवाल उठने शुरू हो गए थे और सवाल उठे भी क्यों न, पाकिस्तान की फितरत ही है धोखबाजी और पीठ में छुरा घोंपने की। सीजफायर के कुछ देर बाद पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन करके आखिर यह जता ही दिया था कि वह धोखेबाज था, धोखेबाज है और धोखेबाज ही रहेगा। आइए जानें कि आखिर पाकिस्तान

सिंधु जल संधि पर अस्थायी विराम

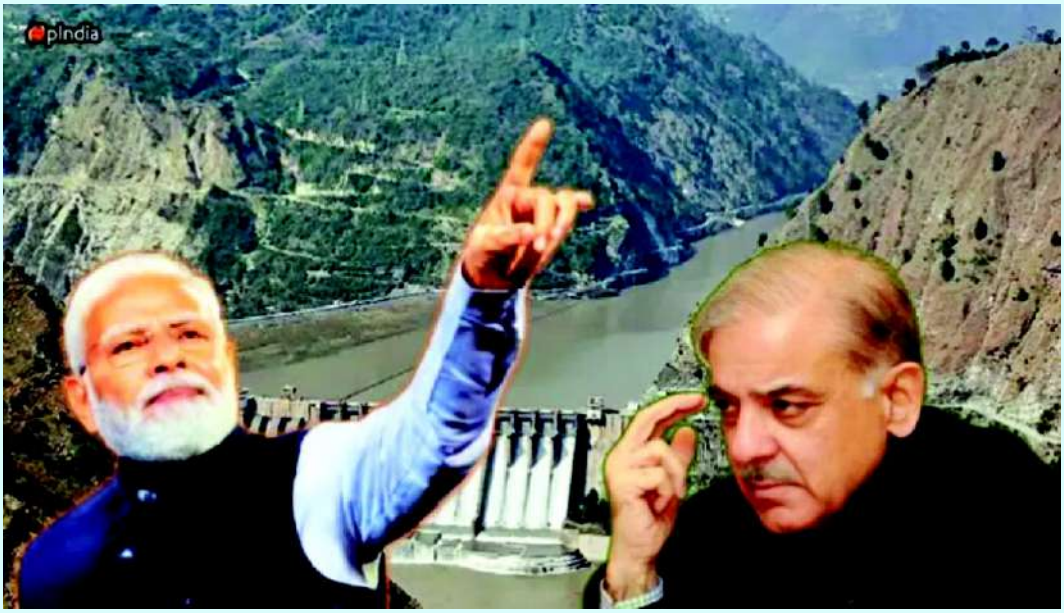

पहलगाम में आम नागरिकों पर पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकी हमले के बाद, भारत सरकार ने घोषणा की कि 1960 के सिंधु नदी जल समझौते को तुरंत स्थगित किया जा रहा है। जल-बंटवारे की यह महत्वपूर्ण संधि तब तक स्थगित रहेगी, जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अनिवार्य रूप से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता। सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे लचीले राजनीतिक समझौतों में से एक रहा है, जो कई युद्धों और तनाव के लंबे दौर में भी चलता रहा है। हालांकि, इसे स्थगित करने का भारत का कदम तनाव के गंभीर होने का संकेत है, क्योंकि ऐसा करने से लंबे समय से चली आ रही वह परंपरा टूटती है, जिसमें जल-बंटवारे के मसले को राजनीतिक और सैन्य तनावों से अलग रखने पर सहमति बनाई गई थी। फिर भी, भारत की यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इसे एक कूटनीतिक कदम कहा जाएगा।

पाकिस्तान के 80 फीसदी खेती सिंधु के पानी पर निर्भर है। भारत मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ पाकिस्तान में बहने वाले पानी का एक हिस्सा ही स्टोर कर सकता है। अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान को जाने वाली सप्लाई को पूरी तरह से बंद करने में कितना समय लगेगा? खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, 2016 में पाकिस्तान प्रयोजित उरी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी, जिसमें 18 भारतीय सैनिक मारे गए थे वह उस वक्त सिंधु जल समझौते का जिक्र कर रहे थे इसके बाद भी पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाए और समझौत पर संकट के बावजूद, भारत ने अब तक इसे रोका नहीं था लेकिन कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद भारत ने पहली बार सिंधु जल संधि समझौता स्थगित कर दिया।

पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता और कितनी बार उसने सीजफायर का उल्लंघन किया है।

अटल जी ने बस यात्रा शुरू की, बदले में मिला कारगिल

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की अनेक उपलब्धियों में लाहौर बस यात्रा को सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना जाता है। आज उस यात्रा

पाकिस्तान के कंट्रोल वाली नदियों का क्या होगा?

भारत ने इस समझौते को तब तक रोकने का फैसला लिया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करता। नई दिल्ली की ओर से यह जवाबी कदम, जिसे भारत-पाकिस्तान संबंधों में निर्णायक पल के रूप में देखा जा रहा है, कुछ अहम सवाल भी पैदा करता है। भारत ने अब सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है, जिसके तहत पाकिस्तान को सिंधु सिस्टम की पश्चिमी नदियों (सिंधु, चिनाब और झेलम) पर कंट्रोल दिया गया है, तो इन नदियों के पानी का वास्तव में क्या होगा? क्या भारत वास्तविक रूप से इसे रोक सकता है और अपने लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकता है? कई बांधों के निर्माण के साथ, भारत कब पाकिस्तान को मिलने वाला पानी पूरी तरह से बंद कर सकेगा? एक्सपर्ट का कहना है कि, हालांकि भारत के पास अब पश्चिमी नदियों पर स्टोरेज और पानी को डायवर्ट करने संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए कानूनी और कूटनीतिक गुंजाइश है। लेकिन तत्काल में पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को डायवर्ट करने की क्षमता मौजूदा बुनियादी ढांचे संबंधी बाधाओं और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को विकसित करने की वजह से सीमित हैं।

पाकिस्तान के लिए संधि के क्या मायने?

पाकिस्तान सिंधु नदी सिस्टम के करीब 93 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करता है और पड़ोसी देश की करीब 80 प्रतिशत कृषि भूमि इसके पानी पर निर्भर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो की ओर से दी गई धमकी से पता चलता है कि सिंधु जल सिस्टम पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए कितना अहम है। भुट्टो ने कहा, 'या तो हमारा पानी इसमें बहेगा या उनका खून बहेगा।

पश्चिमी नदियों का इस्तेमाल नहीं करता भारत

पश्चिमी नदियों पर भारत का उपयोग काफी कम रहा है, जो 330 मेगावाट किशनगंगा और निर्माणाधीन 850 मेगावाट रतले परियोजनाओं

के 24 साल हो गए। वह ऐतिहासिक बस यात्रा 20 फरवरी सन् 1999 में की गई थी। भारत ने दोस्ती और अमन का हाथ बढ़ाया लेकिन बदले में मिला करगिल। लाहौर बस यात्रा वाजपेयी जी की समझदारी और साहस की मिसाल मानी जाती है। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी ऐतिहासिक पहल के कुछ ही महीनों के भीतर भारत और पाकिस्तान एक और जंग में उलझ जाएंगे।

जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक सीमित है, जो पाकिस्तान में नदियों के प्रवाह को बाधित नहीं करते हैं। पश्चिमी नदियों के पहाड़ी भूभाग के कारण इनके जल का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता के बावजूद, इन नदियों पर भारत की मौजूदा स्टोरेज क्षमता जीरो है, जो संधि प्रतिबंधों के कारण सीमित है। हिमालय की नदियों में हाइड्रो पावर कैपिसिटी काफी ज्यादा, जो अनुमानतः 150,000 मेगावाट से अधिक है, क्योंकि उनकी ढलानें तीव्र हैं, प्रवाह बारहमासी है और उद्‌गम ग्लेशियर से होता है। इसलिए भारत की ओर से सिंधु जल संधि को निलंबित करने का मतलब है कि अब उसे पश्चिमी नदियों पर परियोजनाओं के बारे में पाकिस्तान को सूचित नहीं करना होगा, न ही कोई डेटा शेयर करना होगा, और न ही वह पाकिस्तानी अधिकारियों के दौरे पर विचार करेगा, जिससे संधि के तहत सहयोग प्रभावी रूप से रूक जाएगा

चिनाब और रावी नदी पर बड़े प्रोजेक्ट

प्रमुख परियोजनाओं में जम्मू और कश्मीर में चिनाब की सहायक नदी पर पाकल दुल, मारु सुदर (1,000 मेगावाट), चिनाब पर रातले (850 मेगावाट), चिनाब पर कीरू (624 मेगावाट) और चिनाब पर सवालकोट (1,856 मेगावाट) हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं लेकिन पश्चिमी नदियों और उसकी सहायक नदियों पर मौजूदा रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाएं कुछ पानी स्टोर करती हैं। जैसे झेलम नदी के किशनगंगा पर किशनगंगा जलविद्युत परियोजना का जलाशय लगभग 18.35 एमसीएम पानी स्टोरेज करता है। जम्मू स्थित रावी की सहायक नदी पर उझ बहुउद्देशीय परियोजना के पूरा होने के बाद सिंचाई और बिजली के लिए 925 एमसीएम की सकल भंडारण क्षमता पैदा होगी। चिनाब नदी पर बने रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बांध की कुल जल क्षमता 78.71 एमसीएम है। रावी नदी पर निर्मित शाहपुरकंडी बांध, जो अब बनकर तैयार हो गया है, से भारत को सिंचाई के लिए लगभग 1,150 क्यूसेक पानी मोड़ने में मदद मिली है, जो पहले पाकिस्तान में बह जाता था।

नई सिंधु जल संधि की जमीन तैयार करना

- सिंधु जल समझौता भारत के लिए फायदे का सौदा कभी नहीं रहा। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में ये संधि हुई थी। तब भारत चाहता था कि पाकिस्तान की तरफ से हमले होने बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
- 2024 में भारत ने संधि में बदलाव की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा था। भारत सालों से नई सिंधु संधि चाहता है। इससे जलवायु परिवर्तन, पानी की मात्रा जैसे मुद्दों पर भारत अपने हित पर जोर दे सकेगा।
- अब भारत ने घोषित रूप से सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया

जुलाई 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जबरन राष्ट्रपति के पद पर काबिज हुए मुशर्रफ की आगरा में मुलाकात हुई। इस शिखर वार्ता में कश्मीर मसले को लेकर मुशर्रफ के साथ सहमति नहीं बन सकी। मुशर्रफ के अड़ियल रवैये के कारण यह वार्ता पटरी से उतर गई थी। वाजपेयी ने मुशर्रफ से कश्मीर में सीमा पार से होने

है। भारत अपने फायदे का सौदा करने के लिए अब पाकिस्तान को बातचीत के लिए मजबूर कर सकता है।

अपने हिस्से के पानी की हर बूंद का इस्तेमाल करना

- संधि के तहत भारत पूर्वी नदियों का पानी इस्तेमाल कर सकता है। अभी इन नदियों के 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी में से करीब 94 प्रतिशत पानी का इस्तेमाल भारत करता है।
- इसके लिए भारत ने पूर्वी नदियों यानी सतलुज पर भाखड़ा नागल बांध, ब्यास पर पोंग बांध, रावी पर रंजीत सागर बांध और हरिके बैराज, इंदिरा नहर जैसे प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं।
- बाकी करीब 6 प्रतिशत पानी बिना इस्तेमाल हुए पाकिस्तान चला जाता है। बचे हुए पानी के इस्तेमाल के लिए भारत रावी नदी पर शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, सतलुज ब्यास नहर लिंक प्रोजेक्ट और रावी की सहायक नदी पर उझ डैम बना रहा है।
- भारत ने सुनियोजित प्लानिंग कर ली है कि वह इन नदियों का बहाव मोड़कर 100 प्रतिशत पानी अपने यहां इस्तेमाल करेगा।

पाक जाने वाले पूरे पानी को भारत की तरफ मोड़ना

- ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जो सालों चलेगा। मंत्री पाटिल के मुताबिक सबसे पहले नदियों से गाद निकालने का काम किया जाएगा, इससे पानी को रोकना और उसका रुख बदलना आसान होगा।
- नदियों पर बांध और बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जाएंगे। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाएगी।
- पानी को स्टोर करने के लिए जलाशय बनाकर नदियों की दिशा बदलने पर काम शुरू किया जाएगा।

वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कहा था। 2001 में ही भारतीय संसद पर हमला हुआ। इस हमले में पाकिस्तान पोषित लश्कर ए तैयबा और जैश ए मुहम्मद जैसे संगठन शामिल थे। मुशर्रफ ने हमले के काफी सालों बाद यह स्वीकारा था कि वो आतंकवादियों को अपने यहां पर ट्रेनिंग देकर भारतीय सेना से लड़ने के लिए भेजते थे।

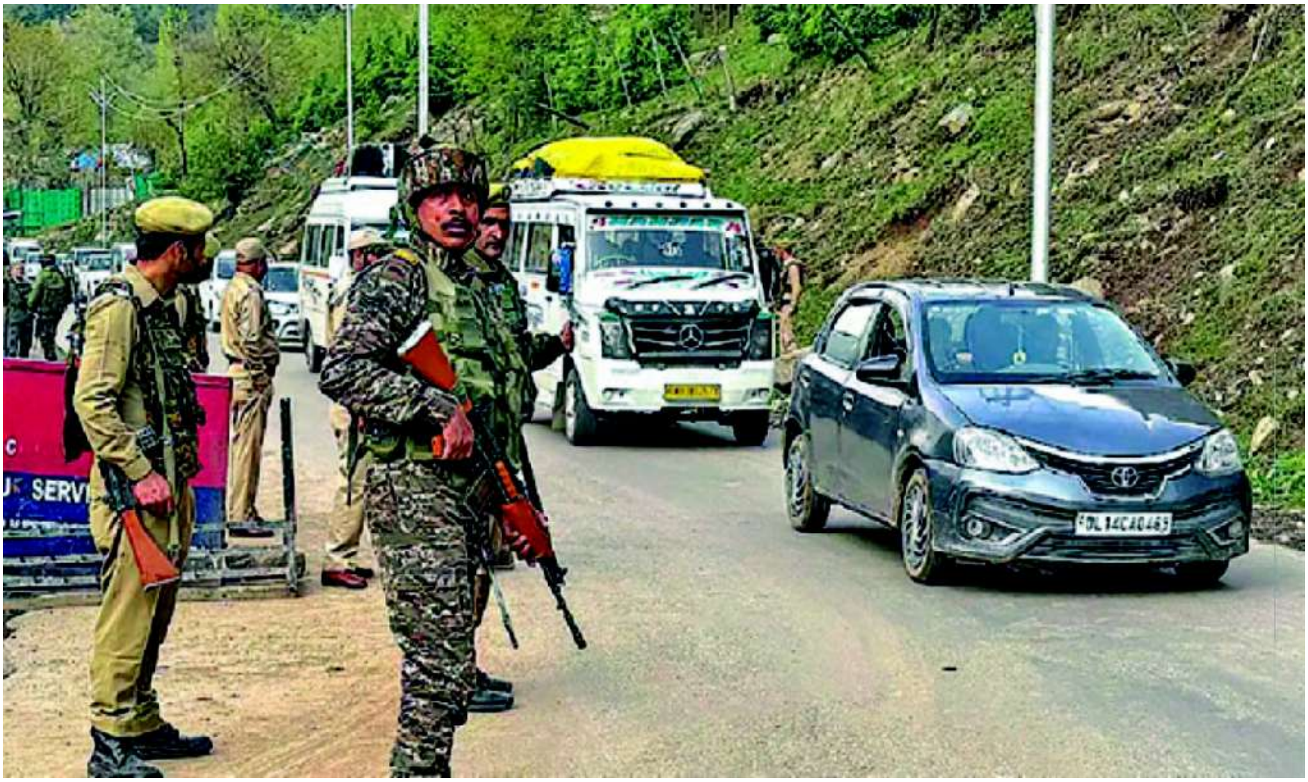

प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह सीमावर्ती इलाकों पर चौकसी बढ़ायें ताकि फिर पहलगाम, पुलवामा और उरी जैसी आतंकी घटनाएं न हो

भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान के संरक्षण में पले-बढ़े टीआरएफ के आतंकियों ने निर्दोष भारतीय पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटनाक्रम के बाद से ही पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। यही कारण है कि देश का हर नागरिक इस निर्मम हत्या का बदला लेने के लिये उत्सुक था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम की बारीकियों को समझा और अंत में इस निर्णय पर पहुंचे कि यह घटना कहीं न कहीं भारत की तरफ से हुए सिक्योरिटी लैप्स के कारण हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री ने उन बहनों के सिंदूर और माताओं के बेटों की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया जिसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की कगार पर खड़ा हो गया है। भारतीय पर्यटकों के साथ हुई इस निर्मम और कायराना हत्या का न सिर्फ भारत ने कड़ा विरोध किया बल्कि विश्व के कई प्रमुख राष्ट्रों ने इस घटनाक्रम पर चिंता व्यक्तकरते हुए भारत के साथ खड़े

होने पर सहमति दी।

सुरक्षा में चूक कैसे, इस पर विचार जरूरी

आज पूरा विश्व इस बात से भलीभांति परिचित है कि पाकिस्तान जैसे कमजोर और गरीब देश के सामने भारत पहाड़ किसी चट्टान से कम नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। एक समय हुआ करता था जब वहां बड़ी संख्या में पुलिस और सैन्य बल तैनात हुआ करते थे। लेकिन अचानक से कैसे राज्य और केंद्र सरकार ने वहां से पुलिस और सैन्य बल को हटा दिया। आखिर सीमावर्ती इलाकों में भारत कैसे इतना बैफिक्र हो गया। इस बात पर हमको एक बार फिर विचार करना चाहिए। क्योंकि यह हमला भारत पर नहीं बल्कि भारत के मान, सम्मान और 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान पर हुआ था।

370 के बाद बैफिक्र तो नहीं हुआ भारत

गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के अनुसार भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया था कि अब कोई आतंकी हमला होने की संभावना नहीं है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने वहां से सीआईएसएफ और सेना के जवानों को वापस बुलाने का निर्णय लिया था। यही नहीं सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने यह फैसला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लिखे गये पत्र के जवाब में किया। अब्दुल्ला ने सरकार से कहा था कि यदि वह पहलगाम से सैन्य बल हटा लेगी तो यहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा और लोगों को रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। लेकिन किसको पता था कि अमित शाह द्वारा लिया गया यह निर्णय एक दिन शाह को ही भारी पड़ेगा और पहलगाम पर आतंकी हमला हो जायेगा।

शाह की बड़ी बातें हुई निराधार साबित

नाम न छापने की शर्त पर विपक्षी दल के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कई बार संसद में बड़े ही गुरूर के साथ इस बात को ताल ठोक-ठोक कर कह चुके थे कि मोदी सरकार में पुलवामा, उरी के बाद कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। जबकि यूपीए की सरकार में 26/11, संसद सहित पुणे ब्लास्ट जैसी कई आतंकी घटनाएं हुई हैं। ऐसे में पहलगाम हमला अमित शाह की बड़ी-बड़ी बातों को निराधार साबित कर चुका है। जाहिर है कि शाह को एक कठोर और गंभीर राजनेता के रूप में जाना जाता है।

ताकि फिर कोई ऐसी घटना न हो

बतौर पत्रकार मैं यही भारत सरकार से निवेदन करती हूं कि यदि भारत के 140 करोड़ लोग बैफिक्र होकर अपने घरों में रह रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा श्रेय भारत की सेना को जाता है। सीमा पर जब सेना के जवान तैनात होते हैं तो दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। ऐसे में अब भारत सरकार को यह चाहिए कि वह अपने सीमावर्ती इलाकों को इस तरह से सुरक्षा से लैस करे कि दोबारा कोई 26/11, पुलवामा, संसद, उरी और पहलगाम जैसा आतंकी हमला न हो।

अब आजाद है बलूचिस्तान

प्रमोद भार्गव

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी लड़ाई में ऐसे साफ संकेत मिलने लगे थे कि पाकिस्तान का भूगोल बदलने जा रहा है। अब बलूच नेता मीर यार बलूच ने ऐलान किया है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से पृथक एक अलग स्वतंत्र देश है। उन्होंने भारत और वैष्विक समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी हेतु समर्थन देने की मांग की है। मीर ने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, इसलिए दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। यह हमारा राष्ट्रीय निर्णय हैं कि हम अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे। बलूच नेता ने भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग और बुद्धिजीवी बलूचों को

पाक का बड़ा भू-भाग बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ रहा था, वह सफलता के शिखर पर है। बलूचिस्तान को नए देश के रूप में मान्यता मिल जाती है तो 1971 के बाद पाकिस्तान की भूमि पर दूसरा बड़ा विभाजन दिखाई देगा। 1971 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना को सैनिक मदद देकर पाक के दो टुकड़े कर दिए थे। 93 हजार पाक सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष हथियार डाल दिए थे। सैनिकों का इतना बड़ा समर्पण इस घटना से न तो पहले कभी हुआ और न ही बाद में?

पाकिस्तान के अपने लोग कहने से परहेज करें। क्योंकि अब हम पाकिस्तानी नहीं बलूचचिस्तानी हैं। बलूचियों ने संयुक्त राष्ट्र से भी स्वतंत्र देश मान लेने का आग्रह किया है।

पाक का बड़ा भू-भाग बलूचिस्तान प्रांत में लंबे समय से स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ रहा था, वह सफलता के शिखर पर है। बलूचिस्तान को नए देश के रूप में मान्यता मिल जाती है तो 1971 के बाद पाकिस्तान की भूमि पर दूसरा बड़ा विभाजन दिखाई देगा। 1971 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की मुक्तिवाहिनी सेना को सैनिक मदद देकर पाक के दो टुकड़े कर दिए थे। 93 हजार पाक सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष हथियार डाल दिए थे। सैनिकों का इतना बड़ा समर्पण इस घटना से न तो पहले कभी हुआ और न ही बाद में ? बलूचों ने तो अपने सीमा क्षेत्र से पाक सैनिकों को खदेड़ कर और सरकारी इमारतों से पाकिस्तानी झंडा उतारकर, बलूचिस्तान का झंडा फहरा दिया। अब बलूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की मांग कर रहे हैं। बलूचों ने संयुक्त राष्ट्र से शांति रक्षक बल भेजने की भी मांग की है। प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता मीर यार बलूच को बलूच के लोगों के अधिकारों की वकालात के लिए जाने जाते हैं। बलूचों ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में शांति रक्षक बल भेजने और पाक सेना को बलूच सीमा क्षेत्र से बाहर कर देने का आग्रह भी किया है। भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाक और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद केवल आतंकी ठिकानों पर लक्ष्य साधकर उन्हें नष्ट किया। परंतु किसी सैन्य ढाचें को निशाना नहीं बनाया। किंतु मीरयार बलूच ने दावा किया है कि बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने डेरा बुगती में पाक के 100 गैस कुओं पर हमला किया। पाक सेना को बंकरों से खदेड़ दिया। अतएव अब पाक सेनाएं, अर्धसैनिक बल, पुलिस, आईएसआई और प्रशासन में कार्यरत सभी गैर बलूच अधिकारी तुरंत बलूचिस्तान छोड़ दें। यदि बलूच स्वतंत्र देष बन जाता है तो भारत-पाक युद्ध के बीच 1971 की तरह एक युगांतरकारी घटना देखने को मिलेगी, जिसमें बलूचों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव में भारत भी भागीदार हो सकता है। बलूचों की स्वतंत्रता की संभावना का अहसास पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री षाहिद खाकान अब्बासी ने भी जताया है। उनका कहना है

भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाक और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद केवल आतंकी ठिकानों पर लक्ष्य साधकर उन्हें नष्ट किया। परंतु किसी सैन्य ढाचें को निशाना नहीं बनाया।

कि बलूचिस्तान पर अब सेना और सरकार का नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। यहां के हालात इतने खराब हैं कि सरकारी मंत्री तक बाहरी सुरक्षा के बिना बाहर नहीं निकल सकते हैं। सेना के जवान अपने ही देश में बंकरों में छिपे हैं।

बलूचिस्तान में विद्रोह की आग चरम पर हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आजादी की मांग करने वाला सबसे पुराना सशस्त्र अलगाववादी संगठन है। यह संगठन पहली बार 1970 में अस्तित्व में आया था। इसने जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल में बलूचिस्तान प्रांत में सशस्त्र विद्रोह का शंखनाद कर किया था। कालांतर में सैनिक तानाशाह जियाउल हक द्वारा सत्ता हथियाने के बाद बलूच नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष विराम की स्थिति बन गई थी। नतीजतन बलूचिस्तान में सशस्त्र विद्रोह खत्म हो गया था और बीएलए का भी कोई वजूद नहीं रह गया था। किंतु कारगिल युद्ध के बाद सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्तापलट कर सत्ता हथिया ली। इसके बाद

बीएलए बलूचिस्तान में चीन के प्रभाव को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता है। उसका मानना है कि चीन बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को हड़पने का काम कर रहा है। इसी नजरिए से ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के साथ एक बड़ा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बना रहा है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलूचिस्तान को बलूचों की इच्छा के बिना बंदूक की जोर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था।

मुशर्रफ के संकेत पर साल 2000 में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाबमिरी की हत्या कर दी गई और मुशर्रफ ने कुटिल चतुराई बरतते हुए पाक सेना से इस मामले में आरोपी के रूप में बलूच नेता खेरबक्ष मिरी को गिरफ्तार करा दिया। इसके बाद फिनिक्स पक्षी की तरह बीएलए फिर उठ खड़ा हुआ। इसके बाद से ही जगह-जगह हमले शुरू हो गए। साल 2020 में एकाएक बीएलए की ताकत बढ़ गई और बलूचिस्तान के सरकारी प्रतिष्ठानों तथा सुरक्षाबलों पर हमलों की संख्या बढ़ती चली गई।

बीएलए बलूचिस्तान में चीन के प्रभाव को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करता है। उसका मानना है कि चीन बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को हड़पने का काम कर रहा है। इसी नजरिए से ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के साथ एक बड़ा चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी बना रहा

है। दरअसल भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलूचिस्तान को बलूचों की इच्छा के बिना बंदूक की जोर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। जबकि वे स्वयं को एक स्वतंत्र देष के रूप में देखना चाहते थे। अतएव पाक की स्वतंत्रता के समय से ही बलूचों का संघर्श पाक सरकार और सेना से निरंतर बना हुआ है। बीएलए जब साल 2000 में वजूद में आया था तब इसके लड़ाकों की संख्या 6000 से भी ज्यादा थी। जिसमें करीब 150 आत्मघाती दस्ते शामिल थे। सरदार अकबर खान बुगती एक समय बलूचिस्तान के सर्वमान्य नेता रहे हैं। इसलिए वे बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 26 अगस्त 2006 को पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने उनकी हत्या कर दी थी। तभी से यह संगठन पाक सेना से लोहा ले रहा है। वर्तमान में बलूच अलगाववादी और तालिबान के बीच निरंतर निकटता बढ़ रही है। वैसे भी अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के काबिज होने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। पाक सरकार ने भी स्वीकार किया है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ही बलूच लड़ाकों को प्रशिक्षित कर रहा है।

पाक की आजादी के साथ बलूचिस्तान का मुद्दा जुड़ा है। पाक की कुल भूमि का 43.6 फीसदी हिस्सा केवल बलूचिस्तान का है। लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किमी है। यहां हिंदु, सिख और ईसाई भी रहते हैं। इनमें आपस में खूब भाईचारा है।

पाक की आजादी के साथ बलूचिस्तान का मुद्दा जुड़ा है। पाक की कुल भूमि का 43.6 फीसदी हिस्सा केवल बलूचिस्तान का है। लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले इस हिस्से में सर्वाधिक बलूच है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किमी है। यहां हिंदु, सिख और ईसाई भी रहते हैं। इनमें आपस में खूब भाईचारा है। भगवान शिव की पत्नी सती का हिंगलाज मंदिर इसी बलूच क्षेत्र में आता है। अनेक मुसलमान भी देवी सती की पूजा-अर्चना करते हैं। क्योंकि ये धर्मांतरित है। यहां से कभी सांप्रदायिक दंगों की खबरें नहीं आती हैं। पाक और बलूचिस्तान के बीच संघर्ष 1945, 1958, 1962-63, 1973-77 में होता रहा है। 77 में पाक द्वारा दमन के बाद करीब 2 दशक तक शांति रही। लेकिन

1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलूच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए। इसे बलूचों ने अपने क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश माना और फिर से संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद यहां कई अलगाववादी आंदोलन वजूद में आ गए। इनमें सबसे प्रमुख बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी प्रमुख है। पीओके और बलूचिस्तान पाक के लिए बहिष्कृत क्षेत्र हैं। पीओके की जमीन का इस्तेमाल वह, जहां भारत के खिलाफ शिविर लगाकर गरीब व लाचार मुस्लिम किशोरों को आतंकवादी बनाने का प्रशिक्षण देता रहा है, वहीं बलूचिस्तान की भूमि से खनिज व तेल का दोहन कर अपनी आर्थिक स्थिति बहाल किए हुए है।

बलूचिस्तान की कलात रियासत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद 27 मार्च 1948 को

1999 में परवेज मुशर्रफ सत्ता में आए तो उन्होंने बलूच भूमि पर सैनिक अड्डे खोल दिए। इसे बलूचों ने अपने क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश माना और फिर से संघर्ष तेज हो गया। इसके बाद यहां कई अलगाववादी आंदोलन वजूद में आ गए। इनमें सबसे प्रमुख बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी प्रमुख है। पीओके और बलूचिस्तान पाक के लिए बहिष्कृत क्षेत्र हैं।

पाकिस्तान में शामिल हो गया था। लेकिन बलूचिस्तान ने पाक में विलय को कभी स्वीकार नहीं किया। लिहाजा यहां अलगाव की आग निरंतर बनी रही है। नतीजतन 2001 में यहां 50 हजार लोगों की हत्या पाक सेना ने कर दी थी। इसके बाद 2006 में अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले 20 हजार सामाजिक कार्यकर्ताओं को अगवा कर लिया गया था, जिनका आज तक पता नहीं है। 2015 में 157 लोगों के अंग-भंग किए गए थे। फिलहाल पुलिस ने जाने-माने एक्टिविस्ट बाबा जान को भी हिरासत में लिया हुआ है। पिछले 20 साल से जारी दमन की इस सूची का खुलासा एक अमेरिकी संस्था ने किया है। वाशिंगटन में कार्यरत संस्था गिलगिट-बलूचिस्तान नेशनल कांग्रेस के सेंग सिरिंग ने मोदी द्वारा उठाए, इस सवाल का समर्थन किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान में लोगों पर होने वाले जुल्म एवं अत्याचार के बाबत पाक को दुनिया के समक्ष जवाब देना होगा ? पाक तो जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन भारत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में भागीदार बने?

युद्ध में सेना जीती, राजनीति हारी

रघु ठाकुर

जैसा कि अनुमान था कि भारत पाकिस्तान के बीच का अघोषित युद्ध कुछ ही दिनों में बंद हो जायेगा, यद्यपि यह भारत की जनता की इच्छा नहीं थी, और न ही किसी भी समझदार व्यक्ति की। क्योंकि आजादी के बाद से लगातार देश पाकिस्तानी सीमा से तनाव-हिंसा और युद्ध झेलता रहा है। इसलिए इस बार लोगों की यह इच्छा थी कि भारत पाकिस्तान के बीच इस संघर्ष का स्थाई हल निकल जाये। इसका मौका भी पाकिस्तान ने स्वयं दिया था जब उसने पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों को आतंकवाद का शिकार बनाया। यह आतंकवादी पाकिस्तान की सेना के ही अघोषित अंग जैसे थे और उसके कई प्रमाण भी मिले। पहलगाम में जो हथियार या गोली बगैरा मिले थे वे भी पाकिस्तानी सेना के थे। भारत के द्वारा प्रत्युत्तर दिए जाने के बाद जो आतंकवादियों के ठिकाने तबाह हुए और जो आतंकवादी मारे गए वे भी पाकिस्तानी सेना के ही थे। क्योंकि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के द्वारा उनके दफनाने और सेना की सैल्यूट के जो फोटोग्राफ स्वतः पाक सेना ने जारी किए थे, उन्हें सारी दुनिया ने देखा है।

पाकिस्तान का पहलगाम आतंकी हमले में हाथ होने का यह स्पष्ट प्रमाण था जिसे झुठलाने की कोई जुर्रत पाकिस्तान नहीं कर सकता। इसलिए जब पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद की समिति की बैठक में इस मामले को उठाया तो सुरक्षा परिषद की समिति के सदस्यों को वह संतुष्ट नहीं कर सका और समिति ने कोई प्रस्ताव नहीं किया। दुनिया के दो छोटे-छोटे देशों ने, जिसमें तुर्किए व एक अन्य देश ने ही पाकिस्तान का समर्थन किया। बाकी पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को अपराधी माना और भारत का समर्थन किया। सुरक्षा परिषद की

समिति में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों ने भारत के पक्ष में समर्थन किया और पाकिस्तान की आलोचना की। यह एक प्रकार से भारत के द्वारा की गई आक्रामक प्रतिक्रिया का समर्थन था। यहां तक कि दुनिया के इस्लामी देशों के संगठन ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। और एक प्रकार से भारत के पक्ष का ही समर्थन किया। इतना बड़ा विश्व जनमत इससे पहले कभी भी भारत के साथ नहीं था। इसलिए देश को उम्मीद थी कि भारत इस बार निर्णायक हल करेगा और सत्तर वर्ष पुरानी त्रुटि में सुधार कर पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेगा। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आतंकवादियों का प्रवेश द्वार पीओके ही है तथा भारत की सीमा से सटे होने की वजह से पाकिस्तान इसका इस्तेमाल एक आधार के रूप में करता है।

लोगों को इस बार इसलिए भी निर्णायक हल की उम्मीद थी क्योंकि लोगों में यह जुमला चलता था कि मोदी है तो मुमकिन है। नरेन्द्र मोदी भी जिस प्रकार पिछले तीन दशकों से आतंकवाद, पीओके, कश्मीर समस्या पाकिस्तान को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों को कोसते रहे हैं, जो कि उचित भी था, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि इस बार नरेन्द्र मोदी अवश्य कुछ निर्णायक कदम उठायेंगे।

घटना के बाद जिस तत्परता से नरेन्द्र मोदी ने बैठकें कीं और गोली के बदले गोला जैसे जुमले फेंके उससे देश बहुत आशान्वित था। परंतु जिस प्रकार अचानक दस मई की शाम को भारत के डीजीएमओ की पाकिस्तान के डीजीएमओ से फोन पर बात हुई और युद्ध विराम का निर्णय हुआ वो न केवल लोगों को आश्चर्यजनक या उम्मीद के परे था, बल्कि श्री नरेन्द्र मोदी की बहादुरी के प्रति निराशा पैदा करने वाला था।

लोगों को इस बार इसलिए भी निर्णायक हल की उम्मीद थी क्योंकि लोगों में यह जुमला चलता था कि मोदी है तो मुमकिन है। नरेन्द्र मोदी भी जिस प्रकार पिछले तीन दशकों से आतंकवाद, पीओके, कश्मीर समस्या पाकिस्तान को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों को कोसते रहे हैं, जो कि उचित भी था, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि इस बार नरेन्द्र मोदी अवश्य कुछ निर्णायक कदम उठायेंगे।

प्रधानमंत्री और उनका एनडीए मात्र 42 प्रतिशत मतों का प्रतिनिधित्व करता है। 58 प्रतिशत उनके और एनडीए के पक्ष में नहीं है। परंतु देश के संसदीय विपक्ष ने और छोटी बड़ी सभी पार्टियों ने बिना शर्त आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार और सेना का समर्थन किया। सारी दुनिया में भारत की एकजुटता का संदेश गया। जबकि पाकिस्तान दुनिया में विभाजित नजर आया। यह एक बड़ी जनतांत्रिक उपलब्धि थी। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने देश की संवैधानिक परम्परा और प्रतिपक्ष का सम्मान नहीं किया। वे भूल गए कि जिन श्रीमती इन्दिरा गांधी को वे और उनकी मातृसंस्थायें तानाशाह कहती हैं उन्होंने भी 1971 में सारे विपक्ष को साथ लेने का प्रयोग किया था। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व से भी सम्पर्क कर सहयोग मांगा था तथा जयप्रकाश को भारत का पक्ष प्रस्तुत करने

के लिए विश्व भ्रमण पर भेजा था। पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ के बीच दस मई की शाम पांच बजे से ही युद्ध विराम हो गया। 12 मई को फिर एक बार टेलीफोन पर औपचारिक चर्चा हुई और सहमति हो गई। इतनी घटनाओं के बाद कल 12 मई को प्रधानमंत्री ने पहली बार देश के समक्ष कुछ बिंदु प्रस्तुत किये। हालांकि उनके आठ मुद्दों में कुछ भी नया नहीं है। बल्कि लगभग वही सब बातें हैं जो सरकारी पक्ष की ओर से पहले भी कही जाती रही थीं।

प्राचीनकाल में सेनायें दिनभर लड़ती थीं, रात में विश्राम करती थीं, अगले दिन की लड़ाई की तैयारी के लिए। यह युद्ध विराम भी कहीं ऐसा ही तो नहीं है जो कुछ दिन के बाद फिर नये रूप रणनीति व ताकत के साथ शुरू हो। इस युद्धविराम के बाद एक और नई बहस शुरू हुई है। वह यह कि भारत ने युद्धविराम का फैसला स्वेच्छा से किया या अमेरिका जैसी विदेशी शक्ति के प्रभाव में। अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति ने तो सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि उन्होंने रात भर भारत पाकिस्तान को समझाया। कुछ इस आशय की खबरें भी आईं कि अमेरिका ने भारत को व्यापार रोकने की धमकी दी। हालांकि भारत सरकार की ओर से इसका औपचारिक खंडन किया गया है। ट्रम्प व मोदी के बीच कौन सच्चा कौन झूठा की बहस होगी तो एक भारतीय होने के नाते मैं मोदी को सच्चा मानूंगा।

यह भी खबरें मीडिया में आई हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु हमले की तैयारी की थी और उसकी सूचना के बाद भारत ने युद्धविराम का निर्णय किया। श्री मोदी के बयान से कि हमें परमाणु युद्ध की धमकी न दें ,भी इस सूचना की पुष्टि जैसी है। मैं नहीं जानता कि यह कितनी सही है। परंतु अगर यह सही है तो फिर भारत के राजनेताओं को यह भी मालूम होना चाहिए कि गांधी-लोहिया-और उनके अनुयायी के रूप मैं यह लिखता कहता रहा हूं कि परमाणु हथियार के बाद भारत पाकिस्तान बराबरी के मुकाबले में आ गये हैं। इसके पूर्व परम्परागत युद्धों में भारत लगातार जीता है, ताकतवर सिद्ध हुआ है। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेई से श्री मोदी तक परमाणु परीक्षण को भारत की महान ताकत बताने वाले संघ को इसका उत्तर देना चाहिए।

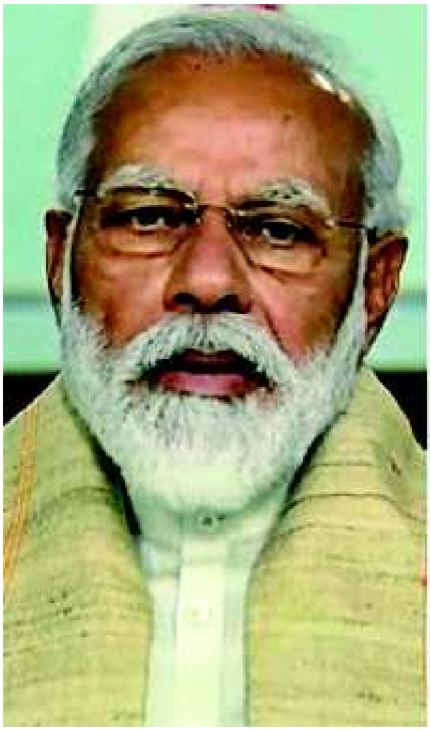

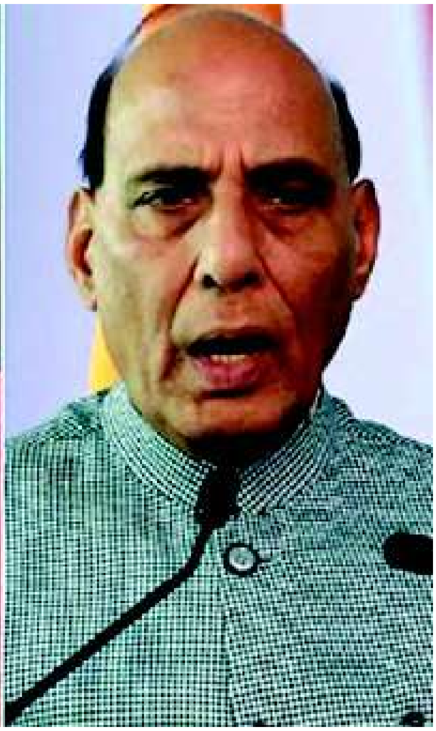

हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने जिस प्रकार अचानक पाकिस्तान को युद्ध के बीच हजारों करोड़ का कर्ज मंजूर किया और आईएमएफ की मीटिंग में भारत अकेला अलग थलग रह गया। दुनिया के सभी सदस्य देशों ने कर्ज मंजूरी को स्वीकृति दी। क्या यह अंतरराष्ट्रीय दबाव बनने का कारण नजर नहीं आता? विश्व शक्तियां केवल अपने स्वार्थ या देश हित को ही लड़ती हैं किसी दूसरे को नहीं। जो प्रधानमंत्री दिन रात

विश्वनेता-विश्वगुरु का खिताब लिए घूमते हैं उन्हें समझना चाहिए कि दुनिया के देश अपने राष्ट्रीय हितों से चलते हैं न कि दूसरे के। तारीफें तो व्यापार के सौदा पटाने की चीज रहती हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता।

हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि देश इस बार मोदी को सच्चा नहीं मान रहा। इसकी वजह भी है कि जब हमला करने का फैसला भारत सरकार के निर्णय के आधार पर हुआ तो युद्ध विराम का फैसला डीजीएमओ कैसे कर सकता है? पाकिस्तान के लिए तो यह माना भी जा सकता है क्योंकि वहां सेना का नियंत्रण है। परंतु भारत में तो सारे निर्णय राजसत्ता ही करती है। यह बात किसी के गले नहीं उतर रही कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री की सहमति के बगैर भारत के डीजीएमओ केवल एक पाकिस्तान के समकक्ष अधिकारी के फोन पर युद्धविराम तय करे। देश के आम लोगों में यह शक है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री ने अपनी नाक उंची दिखाने के लिए यह रास्ता निकाला कि पाक सैन्य अधिकारी फोन करें और भारत का सैन्य अधिकारी उसे मान ले।

अगर यह सैन्य अधिकारी का निर्णय है फिर तो यह भारत की राजनीतिक सत्ता के विरूद्ध विद्रोह जैसा होगा। प्रधानमंत्री को देश को यह बताना चाहिए कि यह युद्धविराम क्यों स्वीकार किया गया। क्या भारत का लक्ष्य पीओके को वापस लेना नहीं है? वो कौनसे कारण हैं जिनके चलते यह युद्धविराम स्वीकार किया, जबकि सरकार के मुताबिक और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत इकतरफा जीत रहा था। यहां तक कि मीडिया के एक बड़े हिस्से के द्वारा तो यह भी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान कांप रहा है, वहां की सेना का मुखिया छिप गया है, वहां के सांसद रो रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री घबड़ा रहे हैं, पाकिस्तान प्यासा मरने वाला है आदि आदि।

मैं मान लेता हूं कि भारत का योग्य और ईमानदार मीडिया यह खबरें सच ही दे रहा था तो उस मीडिया को बताना चाहिए कि एक सप्ताह के संघर्ष व युद्ध से भारत को क्या हासिल हुआ। पाकिस्तान के सौ लोग मरे। भारत के चालीस जवान शहीद हुए। या 26 हत्याओं का बदला सौ को मारकर लिया। ये सब खबरें उत्साह व युद्धकाल की हो सकती हैं परंतु इनसे कोई निर्णायक हल नहीं निकलता।

भारत की सेना ने अपने गौरवमय इतिहास को कायम रखते हुए फिर एक बार निर्णायक युद्ध की ओर कदम बढ़ाया था पर भारत के कमजोर राजनीतिक नेतृत्व, असफल कूटनीति, अदूरदर्शी विदेश नीति, व्यक्तिवाद ने जीते हुए देश व सेना को उसी प्रकार की पराजय की ओर ढकेल दिया है जैसा नेहरू के जीवनकाल में यूएनओ को प्रस्ताव देकर दिया गया था। 1965 में ताशकंद में समझौता स्व. लालबहादुर शास्त्री ने किया था, 1971 में श्रीमति इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता किया था व अटल जी के कार्यकाल में संसद पर हमले के बाद आर-पार के जुमले का हश्र हुआ था। वही अब मोदी के कार्यकाल में गोली बनाम गोला का हश्र हुआ है। सेना जीतती है और राजनीति हारती है। यह भारत की कूटनीति और विदेश नीति की हार है जिसे देश निरंतर झेलने को अभिशप्त है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाक पर मेहरबान क्यों?

किशन भावनानी, एडवोकेट

वैश्विक स्तर पर भारत सहित पूरी दुनियाँ की निगाहें भारत पाक़ तनातनी या युद्ध विराम, फिर सीमा पर जारी गोलीबारी तथा नेताओं की बयानबाजी पर लगी हुई है। इधर भारतीय रक्षामंत्री ने 15 मई को कश्मीर सैनिकों के साथ फिर 16 मई 2025 को गुजरात भुज में एयर फोर्स स्टेशन पर इन दोनों दौरों में आईएमएफ द्वारा पाक के लिए ऋण सेंशन करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए व कहा कि क्या आईएमएफ द्वारा पाक़ को आतंकवाद को वित्त पोषित करने में मदद की जा रही है, उन्होंने मदद पर पुनर्विचार करने की अपील आईएमएफ से की तथा आतंकवाद के हर रूप स्वरूप को समाप्त करने की भी बात कही तथा कहा

> **आईएमफ ने हाल ही में पाकिस्तान को सहायता के तौर पर 1.023 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दूसरी किश्त दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाक को आईएमफ से जो पैसा मिलेगा उसका बड़ा हिस्सा वह अपने देश में आतंकवाद के ढांचे को मजबूत करने में लगाएगा। उन्होंने भारत की तरफ से आईएमफ से यह अपील की है कि वह पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने पर फिर से विचार करे।**

कि आईएमएफ द्वारा प्राप्त वित्त से ध्वस्त किए गए आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़े करने की संभावना है, आगे कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ एक टेलर थी, जरूरत पड़ी तो आगे पूरी तस्वीर दिखाएंगे। तो उधर इस बात का पाक के विदेश मंत्रालय ने तुरंत जवाब दिया, मंत्रालय के बयान में कहा गया, ये गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां पारंपरिक तरीकों से भारतीय आक्रमण के खिलाफ पाकिस्तान की प्रभावी रक्षा और प्रतिरोध के बारे में उनकी गहरी असुरक्षा और हताशा को दर्शाती हैं। पाकिस्तान की पारंपरिक क्षमताएं भारत को रोकने के लिए काफी हैं, बिना किसी सेल्फ इंपोज्ड

न्यूक्लियर ब्लैकमेल के, जिससे नई दिल्ली पीड़ति हैं और कहा कि युद्ध ग्राम 18 मई 2025 तक है। यानें हम देख सकते हैं कि आईएमएफ का ॠण पाक को 14 मई 2025 को मिल चुका है, तो उसके तेवर ही बदल गए हैं यानि अपने कर्ज को चुकाने व आतंकवाद को फिर से पोषित करने की ताकत वित्त के रूप में फिर उन्हें मिली है अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी राशि यानी 1.023 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वाली नीति तो नहीं, क्योंकि भारत जिस तेजी से बुलंदियों के झंडे गाढ़ रहा है उसे विश्व हैरान है। चूँकि आईएमएफ ऋण मिलते ही पाक के सुर बदले और कहा बगैर न्यूक्लियर बम के ही भारत को रोकने में सक्षम है तथा युद्ध विराम 18 मई तक है तथा अमेरिकी दबदबे वाला आईएमएफ पाक पर इतना मेहरबान क्यों? क्या अमेरिका चीन साथ-साथ, वित्त पोषण से फिर सिर उठाएगा आतंकवाद, इसलिए से पाक को मिलने वाली मदद पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पाक इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। उन्होंने यह बात गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन से कही। उन्होंने दुनियाँ से पाक को आर्थिक मदद रोकने की अपील की है। आईएमफ ने हाल ही में पाकिस्तान को सहायता के तौर पर 1.023 बिलियन अमेरिकी डॉलर की दूसरी किश्त दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाक को

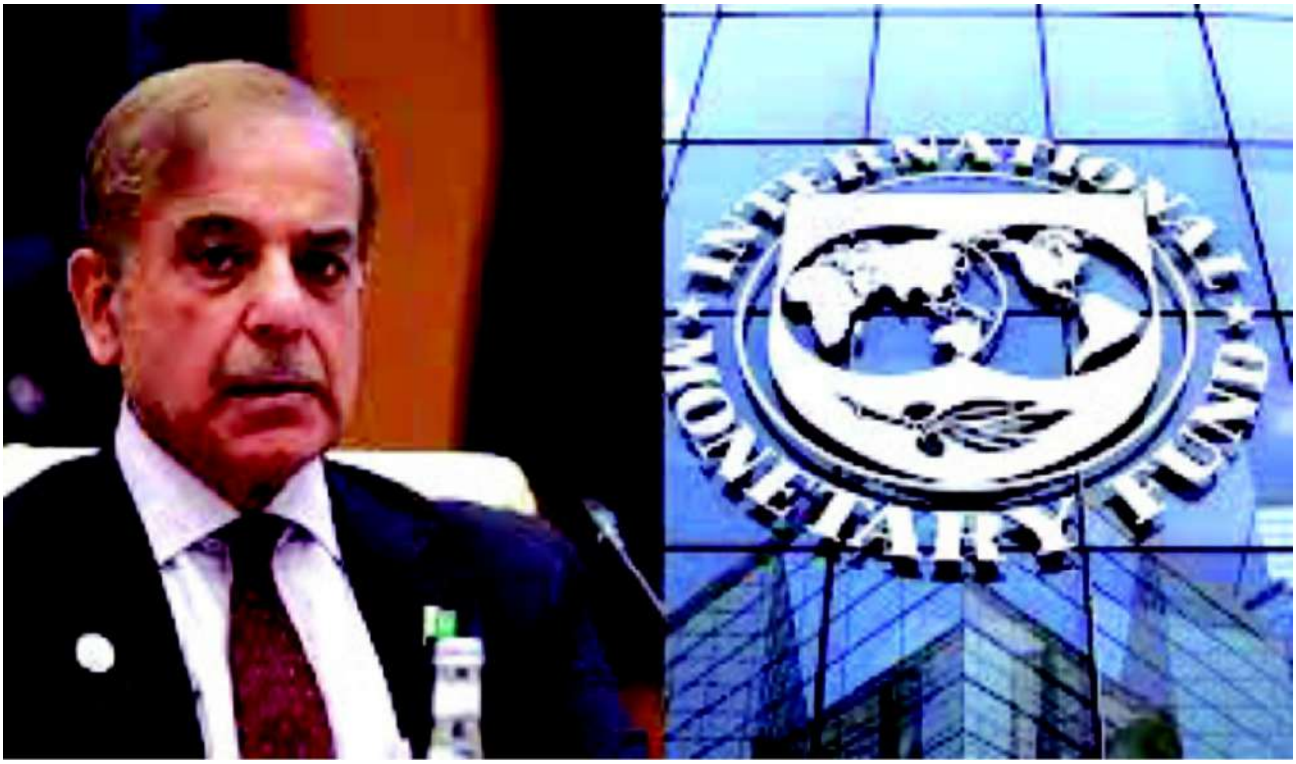

मंजूरी आईएमएफ ने कैसे की और डिलीवरी भी दे दी। मेरा मानना है कि बिना अमेरिका की सहमति से यह बिल्कुल ही नहीं हो सकता? मेरा मानना है कि अमेरिका इसी एक तीर से अनेकों निशाने लगाने की कोशिश कर रहा है, पाक की चीन पर निर्भरता कम करना, चीन को ग्वादरपोर्ट से लेकर चीन पाकिस्तान इकोनामिक कॉरिडोर के कर्ज के पैसे दिलाना तथा कि चीन से बढ़ती यारी और कर दे भारत को दरकिनार आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत का आईएमएफ को दो टूक संदेश,पाक को फंड देने पर पुनर्विचार करें, क्योंकि है आतंकवाद को वित्त पोषण करने की संभावना का सही अनुमान है।

बात अगर हम दिनांक 15 व 16 मई 2025 को रक्षामंत्री द्वारा आईएमएफ को ऋण पर पुनर्विचार की अपील की करें तो उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमफ) आईएमफ से जो पैसा मिलेगा उसका बड़ा हिस्सा वह अपने देश में आतंकवाद के ढांचे को मजबूत करने में लगाएगा। उन्होंने भारत की तरफ से आईएमफ से यह अपील की है कि वह पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने पर फिर से विचार करे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को आईएमफ से जो पैसा मिलेगा, उसका बड़ा हिस्सा वो अपने देश में आतंकवाद फैलाने वाले ढांचे को मजबूत करने में लगाएगा।

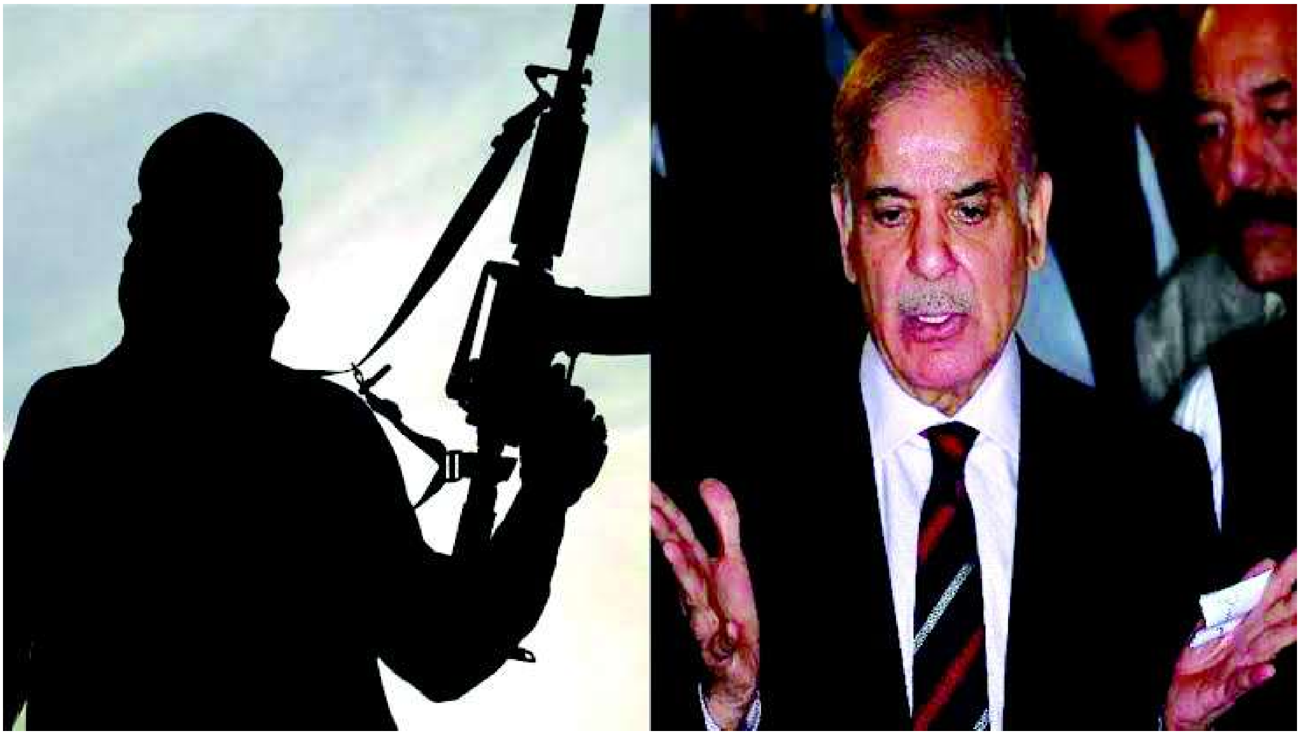

मेरा मानना कि पाकिस्तान इस पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान आईएमफ के बेलआउट पैकेज पर बहुत ही ज्यादा निर्भर है। इस पैकेज से उसे अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद मिली है। पिछले साल पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर था, तब आईएमफ ने उसे 3 बिलियन डॉलर की मदद देकर बचाया था। आईएमफ की वेबसाइट के अनुसार, पाक को सदस्य बनने के बादसे अब तक कम से कम 25 बेलआउट लोन मिल चुके हैं। इस साल अप्रैल के अंत में पाक का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 10.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगस्त 2024 में यह 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अनुमान है कि जून 2025 के अंत तक यह 13.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच पाएगा। आईएमफ ने पाक से कहा है कि वह अपनी जीडीपी का 1.6 प्रतिशत प्राथमिक बजट अधिशेष मानकर बजट बनाए। इसके लिए उसे गैर-ब्याज खर्चों के अलावा लगभग 2 ट्रिलियन रूपये जुटाने होंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अपनी आमदनी बढ़ानी होगी और खर्च कम करने होंगे। अभी पाकिस्तान की स्थिति ये है कि कर्ज चुकाने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। आईएमफ की सहायता पाकिस्तान के लिए अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देती है, पाक अपनी जमीन पर आतंकवादी समूहों को शरण देता है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है। ऐसे में आईएमफ द्वारा दी गई सहायता को आतंकवादियों को मदद देने जैसा माना जाता है। उनका यह बयान पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बढ़ते गुस्से और चिंताओं को दर्शाता है, जो लंबे समय से पाक के आतंकी सरगनाओं के समर्थन के खिलाफ हैं। उन्होंने इस वित्तीय सहायता को आतंकवाद को अप्रत्यक्ष समर्थन देने जैसा करार दिया है।

अभी पाकिस्तान की स्थिति ये है कि कर्ज चुकाने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। आईएमफ की सहायता पाकिस्तान के लिए अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देती है, पाक अपनी जमीन पर आतंकवादी समूहों को शरण देता है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है। ऐसे में आईएमफ द्वारा दी गई सहायता को आतंकवादियों को मदद देने जैसा माना जाता है।

बात अगर हम भारतीय रक्षामंत्री के बयान का तुरंत जवाब पाक विदेश मंत्रालय द्वारा देने की करें तो भारत और पाक के बीच

बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने नया बयान जारी करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच 18 मई तक सीजफायर पर सहमति बनी है। यह अस्थायी युद्धविराम नियंत्रण रेखा पर जारी गोलीबारी को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है, हालांकि भारत की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, भारत की कार्रवाई से पाक की ओर से कहा गया है भारत से रविवार यानी 18 मई तक सीजफायर पर सहमति बनी है, ट्रंप के सीजफायर वाले ऐलान से पहले बीते कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर लगातार हो रही गोलीबारी और ड्रोन हमलों के बीच यह सीजफायर फैसला एक अस्थायी राहत की तरह देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से इस सहमति पर औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। पाक के केंद्रीय बैंक ने बताया है कि आईएमएफ से मिली यह दूसरी किस्त 16 मई को खत्म होने वाले हफ्ते के लिए उसके विदेशी मुद्रा भंडार में दिखाई देगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास अब खर्च करने के लिए कुछ और डॉलर होंगे। पिछले हफ्ते आईएमएफ के निदेशक मंडल ने ईएफएफ प्रोग्राम के तहत 1.02 अरब डॉलर की राशि को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, आईएमएफ ने रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के रूप में 1.4 अरब डॉलर की अतिरिक्त व्यवस्था भी की है।

बात अगर हम आईएमएफ ऋण में अमेरिका चीन के रोल की संभावना की करें तो,इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आईएमएफ से पाकिस्तान को लगातार मिल रहे लोन के पीछे अमेरिका और चीन की बढ़ती करीबी भी एक कारण हो सकती है। इसका भारत पर असर पड़ सकता है। भारत आईएमएफ में पाक को लोन दिए जाने पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुका है। खासकर सीमा पार आतंकवाद के वित्तपोषण में इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर उसने अपना पक्ष रखा है। अमेरिका के दबदबे वाला अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पाकिस्तान पर मेहरबान है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) प्रोग्राम के तहत 1.02 अरब डॉलर (करीब 8,712 करोड़ रूपये) की दूसरी किस्त जारी कर दी है। यह पैसा ऐसे समय पर मिला है जब आईएमएफ पाकिस्तान केआगामी बजट पर ऑनलाइन बातचीत कर रहा है। भारत के साथ तनाव के कारण आईएमएफ के मिशन प्रमुख का इस्लामाबाद दौरा कुछ दिनों के लिए टल गया था। पाकिस्तान सरकार 2 जून को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने की योजना बना रही है।

कांग्रेस के लिये नासूर बने भूपेश बघेल !

कई गंभीर अपराधों और घोटालों में संलिप्पता आने के बावजूद गिरफ्तारी नही

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को सत्ता से बाहर हुए डेढ़ साल बीत चुका है। लेकिन अभी तक बघेल के कारनामों पर ठोस कार्यवाही होती नहीं दिख रही है। पॉच साल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले किए थे उन पर कानूनी कार्यवाहियां बहुत धीमी गति से चल रही हैं। जबकि एक-दो नहीं बल्कि दर्जनों केस अदालतों में चल रहे हैं। देश की सर्वोच्च जाँच एजेंसियां जाँच कर रही लेकिन बघेल अभी तक गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। भूपेश बघेल के कार्यकाल के कई आला अफसर या तो जेलों में है या कानूनी शिकंजे में हैं। छत्तीसगढ़ के कई बड़े घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नामदर्ज एफआईआर के बावजूद गिरफ्तार न होने से जनता हैरान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेपहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भाषणों में साफ किया था कि राज्य में बीजेपी और केन्द्र में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद छत्तीसगढ़ के घोटालेबाज नेताओं की खैर नही। चुन-चुनकर हिसाब लिया जायेगा। जो लूटा है वह लौटाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे जोशीले भाषण के बाद भ्रष्टाचार की मार झेल रही एक बड़ी आबादी बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था। लेकिन केन्द्र और राज्य में बीजेपी के सत्ता में आने के बावजूद बघेल के गिरफ्तारी को लेकर संसय बना हुआ है। सीबीआई, ईडी, आईटी और ईओडब्ल्यू बघेल के खिलाफ कई बड़े घोटालों के लेकर जांच में जुटी है। जांच का सिलसिला करीब तीन सालों से बदस्तूर जारी है। दिलचस्प बात यह है कि घोटालों में सबसे पहले बघेल के गिरोह में शामिल कई बड़े अफसरों और कारोबारियों का नाम सामने आया था। इनके ठिकानों पर छापेमारी के बाद कुछ चुनिंदा आरोपियों के चेहरे देखकर गिरफ्तारियां भी हुई थी और आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं। इन्हीं आरोपियों की तर्ज पर केन्द्रीय जांच एजेसियों ने भूपेश बघेल के पुत्र चेतन्य बघेल फिर इसके बाद भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसियों ने प्रेस नोट जारी कर बघेल के कुकर्मो का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया था। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ 2100 करोड़ के शराब घोटाले, 1500 करोड़ के महादेव एप घोटाले में नामदर्ज एफआईआर दर्ज हुई थी। घोटालों में भी बघेल की संलिप्पता के स्पष्ट प्रमाण एजेंसियों के हाथों में बताये जाते हैं। बावजूद इसके कानून के हाथ प्रदेश के दागी मुख्यमंत्री के गिरेबान तक नही पहुंच पाये हैं। कई बड़े आरोपी हवालात की सैर कर रहे हैं। यहां तक कि बघेल के लिये कमाउ पुत्र साबित हुये तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी जेल की चक्की पीसनी पड़ रही है। लेकिन भूपेश बघेल की गिरफ्तारी को लेकर एजेंसियों को सांप सूंघ गया है। ईडी और सीबीआई के सूत्र तस्दीक कर रहे हैं कि बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश केन्द्र और राज्य सरकार को प्राप्त नही हुये हैं। उनकी यह भी दलील है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपराधों का राजनीतिकरण कर कानूनी दांवपेचों से एजेंसियों की विवेचना को विवादित बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के कई बड़े आरोपियों की याचिकाएं कानूनी पटल पर सुर्खियां बटोर रही हैं। बघेल एण्ड कम्पनियों और उनकी गुर्गो को उनकी पूर्ण विवेचना और कानूनी प्रावधानों की कमजोर कार्यवाही के कारण अदालत कभी ईडी पर सवालियां निशान लगाते हुए ईपीआईआर खारिज कर रही है और जमानत भी दे रही है।

विजया पाठक

आम जनता के बीच सवाल उठ रहा है इतनी सक्षम जांच एजेंसियां आखिर नियम कायदों का पालन न करते हुए जांच को अदालत के पटल पर क्यों रख रही हैं। अदालती कार्यवाही और कानूनी पहलूओं को लेकर कुख्यात घोटालेबाजों को मिली राहत अब गली कूचों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियों में आवाज

निकलने लगी है कि बघेल को गिरफ्तारी से बचाने और अपराधों से बचाने के लिये नौकरशाही का एक धड़ा सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यह सब कुछ प्रभावशील आरोपियों को कानून की गिरफ्त से बचाने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। सूत्र यह भी तस्दीक करते हैं कि आबकारी घोटाला या महादेव ऐप घोटाला में लिप्त आरोपियों के बयान सावधानीपूर्वक दर्ज किये जा रहे हैं। इसमें आरोपी सच उगलने और बघेल का नाम तक लेने परहेज कर रहे हैं। घोटालों में लिप्त आरोपियों को बघेल का नाम न लेने की हिदायत देने जाने का मामला भी जांच एर्जेसियों के गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। फिलहाल बघेल की गिरफ्तारी होती या नही इसे लेकर केन्द्र और राज्य सरकार की मंशा भी प्रजातंत्र के तकाजे पर तोली जाने लगी है।

कांग्रेस के कई नेता यहां भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि बघेल बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गये हैं। पहले अपने पुत्र चैतन्य को बचाने के लिये अब फिर खुद के बचाव में पार्टी की आंखों में धूल झोंकना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेसी नेताओं की आंशका यूं ही नही बनाई जा रही है। वो दावा करने में भी नही चूक रहे हैं कि किसी गोपनीय करार के तहत बघेल ने उत्तर प्रदेश चुनावी प्रभारी रहते हुये करीब 32 ऐसे उम्मीदवारों को कांग्रेस की टिकट दिलवाई थी, जो बीजेपी उम्मीदवारों के सामने बिलकुल टिक नही पाये। नतीजतन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई थी। कांग्रेस गलियारों में मेरठ विधानसभा की सीट पर अर्चना गौतम की उम्मीदवारी का प्रकरण आज भी यूपी के आम कार्यकर्ता नही भूल पाये हैं। बताया जाता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, फेम बनाकर कांग्रेस नेता के रूप में अर्चना गौतम की तापपोशी की थी। हालांकि परिणाम पार्टी के सामने रहे। अर्चना गौतम की जमानत जप्त हुई और कांग्रेस चौथे नंबा

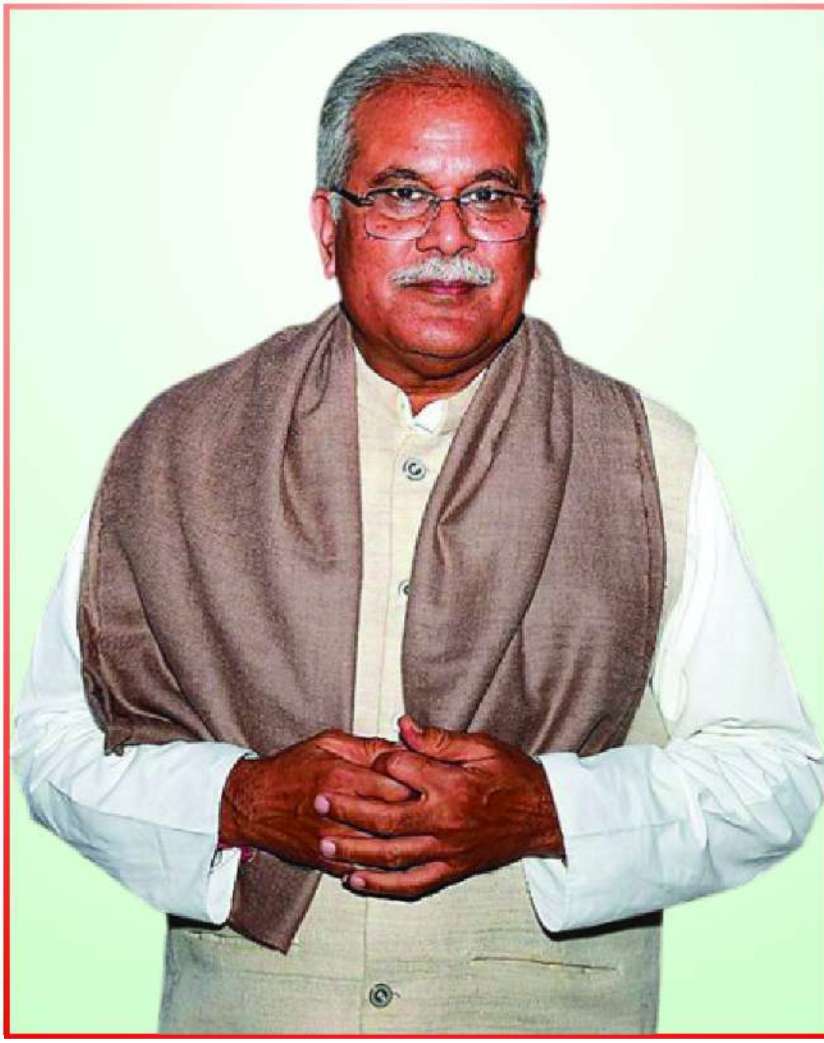

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कारनामों को लेकर कुख्यात हैं। दर्जनों घोटालों में उनका नाम सामने आ चुका है। ईडी, ईओडब्ल्यू की जांचों में साबित भी हो चुका है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार में वो शामिल हैं। लेकिन यहा सवाल उठ रहा है कि आखिर अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। क्या भूपेश बघेल को किसी तरह का अभयदान मिल रहा है। क्या जान बूझकर बघेल को बचाया जा रहा है। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है।

क्या चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव के हाथों में सौंपना चाहिए कांग्रेस की कमान?

अब समय आ गया है कि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल को बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह चरणदास महंत या टीएस सिंहदेव को कमान दे देना चाहिए। यही वह समय है जब प्रदेश में कांग्रेस के अस्तित्व को बचाया जा सकता है। नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। छत्तीसगढ़ का हाल भी मध्यप्रदेश या राजस्थान जैसी हो सकती है। जिस ढंग से बघेल ने पांच वर्षों के कार्यकाल में राज्य में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया उसके बाद तो पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ने की स्थिति बन गई है। अगर पार्टी आलाकमान समय रहते नहीं चेता तो वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस का अस्तित्व मप्र, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, भूपेश बघेल के कार्यकाल की बारीकी से समीक्षा करें और आंखों पर बंधी पट्टी को खोलकर उनका विश्लेषण उपरांत यह तय करें कि बघेल को किस तरह से पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है। क्योंकि यदि पार्टी में बघेल जैसे भ्रष्टाचारी नेता रहे तो वह दिन दूर नहीं जब पार्टी आगामी चुनाव में जनता के दरवाजे पर जाने लायक भी नहीं बचेगी।

से भी पीछे खिसक कई। इसके उपरांत बघेल की निगरानी में असम, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। बघेल ने इन राज्यों में जिन इलाकों में प्रचार किया था और जिन कांग्रेसियों को टिकट दिलवाई उनका सूपड़ा

कानूनी दांवपेचों के चलते सदमे में जांच एजेंसियां

छत्तीसगढ़ में आईटी, ईडी और सीबीआई की धमक से प्रशासनिक गलियारे से लेकर कई राजनीतिक दलों के दफ्तरों में हलचल तेज देखी जा रही है। एक ओर जहां कांग्रेस अपने नेताओं के बचाव में जुटी है वहीं बीजेपी भ्रष्टाचार के मामलों को गिन-गिन कर उजागर कर बघेल सरकार के 05 साल के कार्यकाल की यादों को तरोताजा करने में नही चूक रही है। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री बघेल गिरफ्तार होंगे या नही? राज्य में भ्रष्टाचार के मसीहा के रूप में बघेल को देखा जाता है। उन्हें उनकी काली करतूतों को लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरते डेढ़ साल बाद भी बघेल कानून की गिरफ्तारी से अछूते बताये जाते हैं। उनके ठिकानों पर सीबीआई समेत अन्य जांच एजेंसियों दबिश दे चुकी हैं। बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी राजनैतिक गलियारों में यक्ष प्रश्न के रूप में देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद गिरफ्तारी की तलवार का इंतजार लम्बा हो चला है। बताते हैं कि जांच एजेंसियों के पास बघेल की भ्रष्टाचारों की लंबी फेहरिस्त उपलब्ध है। महादेव एप घोटाला हो, शराब घोटाला हो पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की भूमिका भ्रष्टाचार के नायक के रूप में देखी जा रही है। सूत्र तस्दीक करते हैं कि बघेल के खिलाफ पुख्ता सबूतों के आधार पर सीबीआई के छापेमारी तो की लेकिन उनकी गिरफ्तारी लगातार टलती रही। जानकार यह भी बताते हैं कि बघेल को हाजिर होने के लिए सीबीआई और ईडी की ओर से अभी तक कोई समन जारी नही किया गया है। यही हाल बघेल के खिलाफ एसीपी ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरणों का बताया जाता है। सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले में शामिल कारोबारी और आबकारी अमले के महत्वपूर्ण अधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के नाम का परहेज बररते हुए अपने बयान दर्ज कराये हैं। नतीजतन बघेल को कानूनी दांवपेचों का मिलता फायदा प्रदेश की साफ हो गया।

बघेल को बताते हैं बीजेपी का स्लीपर सेल

बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता उन्हें का बीजेपी का स्लीपर सेल बताने में भी पीछे नही हैं। उनका दावा है कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग से छुटकारा पाने के लिये बघेल ने कांग्रेस को बीजेपी के हाथों गिरबी रख दिया है। उनके मुताबिक

प्रशासनिक क्षमता पर सवालियां निशान लगाया है। महादेव एप सट्टे घोटाले से बघेल का नाम प्रमुख कड़ी के रूप में सामने आया है।

दुबई में बैठे सटोरी सौरभ चंद्राकर ने वकायदा वीडियो जारी कर दावा किया था कि महादेव एप सट्टा कारोबार को संरक्षण देने के एवज में तत्कालीन मुख्यमंत्री बघेल को लगभग 500 करोड़ रुपये सौंपे गये थे। ईडी के कई आरोपियों ने भी बघेल का नाम दर्ज कराते हुए अपने बयानों में साफ किया है कि शराब घोटाले, महादेव एप घोटाले में भूपेश बघेल भी शामिल थे। बघेल के अलावा पुलिस के दर्जनों अधिकारियों को संरक्षण देने के एवज में हर माह लाखों रुपये जाता था। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने ईडी को दिये अपने बयानों में स्पष्ट किया है कि सटोरियों के द्वारा तय की गई रकम के हर माह लगभग आधा दर्जन अफसरों को सौंपा करते थे। बताते हैं कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में घिरे बघेल की गिरफ्तारी को लेकर एजेंसियां पसोपेश में बताई जाती है। केन्द्रीय कर्मचारियों के रुख से भी अब तक स्पष्ट नही हो पाया कि बघेल पर कानूनी शिकंजा कसेगा कि नही। फिलहाल तो बघेल और उनकी टोली कानूनी दांवपेचों से केन्द्र और राज्य सरकार की जांच एर्जेसियां दो चार हो रही हैं। बघेल के दोनों हाथ अभी भी घी में और सिर कढ़ाई में बताया जाता है। यह देखना गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में लपेटे में आये भूपेश बघेल पर कानून का शिकंजा कब कसेगा।

तमाम मामलों में फंसे बघेल का राजनीतिक कैरियर भी दांव पर लगा है। यदि बघेल इन मामलों में फंसते हैं तो निश्चित रूप से उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो जायेगी। बताया जाता है कि आने वाले समय में बघेल के दिन अच्छे नहीं हैं।

बघेल शासन के अधिकतर अधिकारी जेल में

भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में पांच साल शासन किया। इन पांच साल में भूपेश बघेल ने कई भ्रष्टाचार किये। इतना ही नहीं उनके शासन के अधिकतर अधिकारी कानूनी शिकंजे में फंसे हैं। कई तो जेल में हैं या जमानत पर हैं। मतलब साफ है कि बघेल तो भ्रष्टाचार में शामिल रहे उनके अधिकारी भी अछूते नही रहे। बघेल की खास सौम्या चौरसिया पर तो कई गंभीर आरोप लगे हैं। और अभी भी जेल में है। पांच साल में ऐसे कारनामें किये कि आज छत्तीसगढ़ बघेल के शासनकाल को भ्रष्टाचार के रूप में देखता है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके ज्यादातर उच्च अधिकारी कानून के शिकंजे में फंसे हैं।

केन्द्रीय स्तर पर बघेल को संरक्षण के चलते बघेल की गिरफ्तारी पर रोक है। छत्तीसगढ़ में सफाई की ओर बढ़ चुकी कांग्रेस को बचाने के लिये प्रदेश में नये नेतृत्व की मांग जोरों पर है। अब कार्यकर्ता महंत जैसे नेताओं के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। जबकि पार्टी के भीतर बघेल को जयचंद की पदवी से नवाजा जा रहा है। इधर बघेल की गिरफ्तारी न होने से बीजेपी संगठन ने भी

गहमागहमी देखी जा रही है। विधानसभा के पूर्व बघेल के लिखाफ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने लंबी चौड़ी शिकायतें केन्द्र, राज्य सरकार और जांच एजेंसियों को की थी। यह शिकायतें रंग भी लाई। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले का लेखाजोखा मांगा था। लेकिन नौकरशाही के चर्चित धड़े ने आरटीआई के प्रावधानों को भी साथ-साथ में रखकर सूचनाएं प्रदान करने पर भी रोक लगा दी। सरकारी और गैर सरकारी ठिकानों से सबूतों को नष्ट करने का उपक्रम भी शुरू कर दिया। इस पर रोक लगने से सरकार को अपेक्षित कामयाबी नही मिल पाई। ऐसे संघर्षों के दौर में प्रदेश के कई पत्रकारों ने बघेल सरकार के अपराधों और घोटालों को उजागर करने के लिए एजेंसियों और अदालत के संज्ञान में लाया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में आने के बावजूद बघेल की गिरफ्तारी को लेकर जारी आंख मिचोली का खेल यूं ही जारी है। बीजेपी के कई नेता स्वीकार्य कर रहे हैं कि कहीं न कहीं बघेल को अनुचित संरक्षण होने से उनकी गिरफ्तारी लगातार टाली जा रही है। मुख्य

छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता में आने के बावजूद बघेल की गिरफ्तारी को लेकर जारी आंख मिचोली का खेल यूं ही जारी है। बीजेपी के कई नेता स्वीकार्य कर रहे हैं कि कहीं न कहीं बघेल को अनुचित संरक्षण होने से उनकी गिरफ्तारी लगातार टाली जा रही है।

छत्तीसगढ़ में जब तक भूपेश बघेल रहेंगे कांग्रेस खत्म होती रहेगी

कभी छत्तीसगढ़ में जनता के दिलों पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का आज पतन होता दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस आलाकमान की उदासीनता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार और अनाचार। पिछले पांच वर्षों में सत्ता रहते हुए जिस तरह का जनता पर अनाचार भूपेश बघेल ने किया वैसा व्यवहार आज तक कांग्रेस के किसी भी राजनेता और मुख्यमंत्री ने नहीं किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का एक लंबा कार्यकाल रहा है। अपनी स्थापना से लेकर लगातार कुछ वर्षों तक पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी के नेतृत्व ने पार्टी ने न सिर्फ अपनी एक शाख स्थापित की, बल्कि प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर भी किया। लेकिन समय के साथ वरिष्ठ नेताओं को पार्टी ने किनारे लगा दिया और बघेल जैसे नेता आज भी पुष्पित पल्लवित होते दिखाई दे रहे हैं। एक बात जो हैरान करने वाली है वह यह कि आखिर भूपेश बघेल के पास गांधी परिवार का ऐसा कौन सा राज है कि राहुल गांधी से लेकर सोनिया और प्रियंका भी बघेल के खिलाफ कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात चाहे प्रदेश संचालन की हो या फिर पार्टी का नेतृत्व करने की। राज्य के नेतृत्व से लेकर पार्टी के नेतृत्व तक हर स्थान पर बघेल असफल हुए और उन्होंने सिर्फ पार्टी को नुकसान ही पहुंचाया है और आज भी नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। यह भी सच है कि जहां-जहां पार्टी आलाकमान ने भूपेश बघेल को जिम्मेदारी सौंपी वहां-वहां कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ हुआ है। हमने ऐसे कई उदाहरण देखें हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान को आज तक यह बात समझ नहीं आ रही है।

आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं जबकि सह आरोपी जेल की हवा खा रहे हैं। प्राप्त खबरों के मुताबिक संगठन के बड़े नेता बघेल की गिरफ्तारी के पक्ष में खड़े हैं। जबकि सरकार में शामिल मुख्यधारा के नेताओं को केन्द्र की झरी झंडी का इंतजार है। उनकी यह भी दलील है कि उपर से आदेश मिलते ही बघेल को लेकर धर दबोचा जायेगा लेकिन आदेश तो मिले। ऐसे नेता एजेंसियों को

आरोपियों को धड़ पकड़ कानूनी स्वतंत्रता को जायज ठहरा रहे हैं। उनका दावा है कि जांच एजेंसियों को कहीं न कहीं बघेल की गिरफ्तारी की राह तक रहे हैं। उन्हें भी पार्टी के उचित फोरम से बघेल की गिरफ्तारी के स्पष्ट आदेशों का इंतजार है।

छत्तीसगढ़ में प्रो. विनोद शर्मा पर हमले का मामला

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जहां पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर ईडी और ईओडब्ल्यू में अपने कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों के कारण उन्हें आशंका है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। वहीं अब उनके बेटे ने उनके लिए एक नई मुसीबत को जन्म दे दिया है। दरअसल भिलाई में हुए हत्या की साजिश के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का नाम सामने आ रहा है। हालांकि राज्य का गृह विभाग उनके सुपुत्र को पूरी तरह बचाने में जुटा हुआ है। यही कारण है कि अब तक इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यही नहीं राज्य की जनता और सत्ताधारी दल के कई नेता इस बात को

> **भिलाई में हुए हत्या की साजिश के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का नाम सामने आ रहा है। हालांकि राज्य का गृह विभाग उनके सुपुत्र को पूरी तरह बचाने में जुटा हुआ है। यही कारण है कि अब तक इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है।**

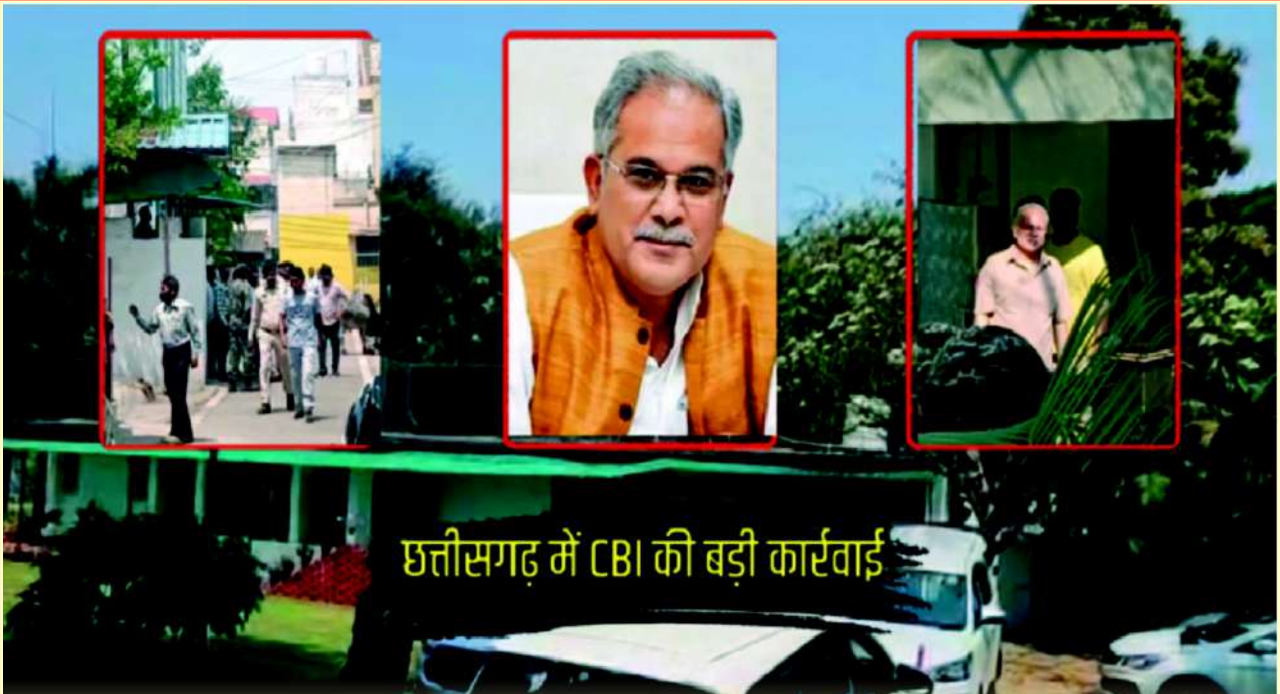

बघेल के 14 ठिकानों पर एक साथ मारे छापे

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने 14 ठिकानों पर रेड की है। चैतन्य के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। छापेमारी छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में की गई है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेश बघेल के बेटे का नाम भी सामने आया है। ईडी ने चैतन्य बघेल के ठिकानों सहित छत्तीसगढ़ में 14 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। बता दें कि कथित शराब घोटाले को लेकर आरोप है कि इसमें 2019 और 2022 के बीच राज्य के खजाने से करीब 2,161 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान एजेंसी को ऐसे सबूत मिले हैं, जिनका संबंध चैतन्य बघेल से है। एजेंसी ने मौजूदा सबूतों को तलाशी का आधार बताया है। ईडी की जांच में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, राजनेताओं और आबकारी विभाग के अधिकारियों से जुड़े एक नेटवर्क का भी पता चला है।

लेकर चिंतित हो रहे हैं कि आखिर सरकार इस आरोपी सुपुत्र जिसने गुंडे के समान कार्य किया है, उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मामला ऑनर किलिंग का है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर मुख्य आरोपी/षडयंत्रकर्ता जो पूर्व मुख्यमंत्री का लड़का है, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हासिल कर लिए हैं। बस मामला राज्य के गृह विभाग के मुखिया की हरी झंडी के लिए अटका हो। मुमकिन है कि इस मामले में कोई कार्यवाही ही ना हो। इसके साथ ही पूरे भिलाई क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र के काले कारनामों की चर्चा हो रही है। उनका आतंक पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। लोग भी उसके कारनामों से परेशान हैं।

दुर्ग-भिलाई में आतंक मचा रखा है पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र ने

दरअसल भिलाई तीन के डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर

आखिर कब मिलेगा छत्तीसगढ़ को इंसाफ

पूर्व मुख्यमंत्री और अधिकारियों को भाजपा सरकार क्यों दे रही अभयदान?

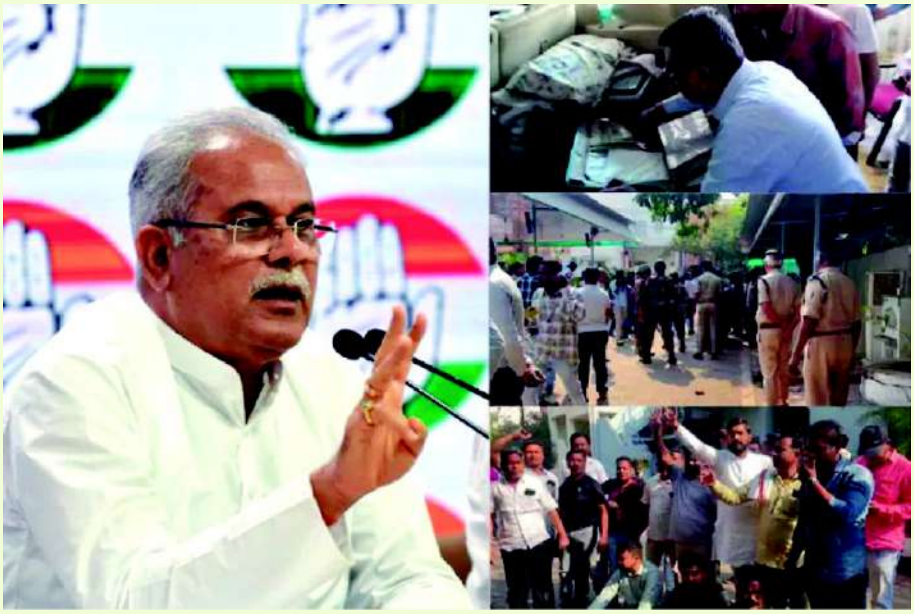

किसी भी राज्य में सत्ताधारी दल के प्रमुख नेता से राज्य की जनता यह अपेक्षा करती है कि वह उसके हित में फैसला करे, राज्य को विकास के पथ पर ले जाए और प्रदेश के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। लेकिन भूपेश सरकार के समय राज्य में उनके करीबी नेता और अफसरों द्वारा किए गए गुनहगारों पर विष्णुदेव सरकार फिलहाल कोई कार्यवाही करती दिखाई नहीं दे रही है। आलम यह है कि राज्य की जनता में असंतोष फैलता जा रहा है और दोषी खुलेआम शहर में घूम रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी सरकार के नेता बघेल सहित सभी दोषियों को अभयदान दे रहे हैं। अगर साय सरकार ने जल्द इन नेता और अफसरों की जुगलबंदी पर कड़ी कार्यवाही नहीं की तो दूसरे नेता और अफसरों के हौंसले बुलंद होंगे और वे भी राज्य को खोखला करने की दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। यही नहीं ये सब वही नेता हैं जो एक समय पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की नीतियों पर कटाक्ष करते और उन्हें बुरा भला कहने से तनिक नहीं हिचकते थे। इससे आगे जब इस बार संसद में केंद्र की भाजपा सरकार मुश्किल में नजर आई तब महादेव सट्टा को लेकर सांसद संतोष पांडे पूरे विपक्ष को महादेव सट्टा को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लेकर घेरा, उनके साथ उन अधिकारियों को भी घेरा। संतोष पांडे कांग्रेस को इस मुद्दे पर कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया पर राज्य की विष्णुदेव साय की सरकार ने इन दागियों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

साय सरकार ने दे रखी है कांग्रेस के खास दागियों को प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी

जानकारी के मुताबिक जिन अफसरों ने भूपेश बघेल शासन में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया और राज्य को खोखला करने में भूपेश

विनोद शर्मा की डंडे से पिटाई करने वाले तीन आरोपी भिलाई पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ये तीनों ही आरोपी मध्यप्रदेश रीवा के निवासी हैं। इस पूरे मामले में पांच आरोपी हैं। 19 जुलाई को भिलाई तीन के खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय के हिन्दी के प्रोफेसर विनोद शर्मा को मोटर साइकिल सवार चार नकाबपोश बदमाशों ने डंडा से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। प्रोफेसर का कार चालक जब बचाने गया तो उसकी भी पिटाई कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 109, 296,

बघेल की मदद की है साय सरकार उन अफसरों को सलाखों के पीछे भेजने के बजाय उन्हें मलाईदार पोस्टिंग देने में जुटी हुई है। यह वही अफसर हैं जिनके उपर कई प्रमुख योजनाओं में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। इन अफसरों के खिलाफ ईडी सहित आयकर विभाग ने भी बड़ी कार्यवाही की है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दो मामलों में केस दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन के आधार पर अब तक 04 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट पर एसीबी ने कस्टम मिलिंग मामले (चावल घोटाला) और डीएमएफ मामले में एफआइआर दर्ज की है। डीएमएफ मामले में एसीबी ने ईडी की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में ईडी ने आरोप लगाया है कि निविदाओं के आवंटन में बड़े पैमाने पर पैसों की गड़बड़ी की गई है। खासतौर पर दो आईपीएस अफसर जो कि सुपर सीएम की भूमिका में थे, जिन पर महादेव सट्टा को लेकर चार्जशीट सहित अन्य में उल्लेख है उनको उल्टा एलिवेट कर दिया गया है।

क्या भ्रष्ट अफसरों को भाजपा से मिली माफी ?

राज्य में भाजपा सरकार के गठन के बाद इन अफसरों पर एक्शन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हर कोई इस बात पर ही चर्चा कर रहा है कि आईपीएस आरिफ शेख़, आनंद छाबरा सहित अनिल टुटेजा, पूर्व जनसंपर्क आयुक्तदीपांशु काबरा जैसे अफसरों पर कार्यवाही होगी या इन्हें अभयदान दिया जायेगा। गौरतलब है कि भूपेश बघेल की सरकार में इन अफसरों ने चौतरफा भ्रष्टाचार किया और राज्य को जबरदस्त ढंग से लूटा है। बघेल सरकार में कुछ खास काम तो इन्हीं अफसरों को दिये जाते थे। जैसे भाजपा नेता, पत्रकार के हर मूवमेंट की खबर रखना आदि। साथ-साथ क्या साजिश रची जा सकती है, उसका खाका खींचने में भी इनका ही हस्तक्षेप होता था। पत्रकारिता के माध्यम से मैंने उनके बारे में काफी उल्लेखित किया। फिर भाजपा ने भी इन दोनों अधिकारियों से तंग आकर मुख्य चुनाव आयुक्तसे 120 पन्नों की आरिफ शेख़ की शिकायत की और आनंद छाबड़ा की 48 पन्नों की कंप्लेंट की थी। बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार अब जीरो करप्शन टॉलरेंस जो प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है उस पर चलकर तंत्र का दुरुपयोग करने वाले ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही करेगी या फिर इन्हें अभयदान दिया जायेगा।

3(5), 351(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरूकी। इस मामले में पांच आरोपियों की पहचान भिलाई तीन पुलिस ने करते हुए तीन को गिरफ्त में ले लिया है।सूत्रों के मुताबिक पकड़े गये आरोपियों ने एक जगह किसी बिटटू नाम के व्यक्तिका जिक्रभी किया है।

महादेव सट्टा ऐपः एक नजर में

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने महादेव बेटिंग एप केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी आरोपी के रूप नामजद किया है। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई

एफआईआर में अब भूपेश बघेल के नाम का भी जिक्र है। इस मामले में सीबीआई ने भूपेश बघेल समेत कुल 21 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के विभिन्न ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी को अंजाम दिया था। सीबीआई ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में एक साथ 60 जगहों पर छापेमारी की और उसकी टारगेट पर मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल थे। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने एफआईआर में महादेव सट्टा एप के संचालक प्रमोटर रवि उप्पल सौरभ चंद्राकर शुभम सोनी और पिंटू चंद्रभूषण वर्मा असीम दास सतीश चंद्राकर नीतीश दीवान अनिल अग्रवाल विकास क्रिया रोहित गुलाटी विशाल आहूजा धीरज अहूजा

अनिल अंबानी सुनील दमानी सिपाही भीम सिंह यादव, हरिशंकर ट्रिब्लेवाल, सुरेंद्र बागड़ी सूरज चोखानी पुलिस अधिकारी पूर्व सीएम के OSD और निजी व्यक्ति शामिल हैं।

महादेव ऐप से जुड़े धनशोधन मामले की जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय

गौरतलब है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) महादेव ऐप से जुड़े धनशोधन मामले की जांच कर रहा है, जिसका खुलासा राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था। ईडी ने पहले भी राज्य में इस मामले में कई छापे मारे थे और अवैध सट्टेबाजी व गेमिंग एप के दो मुख्य प्रवर्तकों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ अभियोजन शिकायतें (आरोप पत्र) दायर की थीं।

क्या है ये एप?

महादेव बेटिंग एप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया था। इस पर यूजर्स पोकर जैसे कार्ड गेम्स और अन्य गेम खेल सकते थे। इस एप के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, जैसे खेलों में सट्टेबाजी भी की जाती थी। इसकी शुरु आत 2019 को छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर ने की थी।

अब तक क्या हुआ?

हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब घोटाले के मामले में बघेल के आवास पर छापेमारी की थी। राज्य सरकार ने पिछले साल सीबीआई को कथित महादेव घोटाले से संबंधित विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज 70 मामले और राज्य में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) में दर्ज एक मामला सौंप दिया था।

छत्तीसगढ़ का शराब घोटालाः एक नजर में

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शराब घोआले में भी फंसे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने पूर्व सीएम और उनके बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े 14 परिसरों पर छापेमारी की थी। दावा है कि 2100 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले में

चैतन्य बघेल को भी कथित तौर पर फायदा पहुंचाया गया। यह छापेमारी कथित शराब घोटाला मामले में उनके बेटे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई (दुर्ग जिला) स्थित ठिकानों, चैतन्य बघेल के कथित करीबी सहयोगी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल और कुछ अन्य के ठिकानों पर भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की गई थी।

ये दिग्गज हुए थे गिरफ्तार

ईडी ने इस मामले में जनवरी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा के अलावा रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) अधिकारी अरु णपति त्रिपाठी और कुछ अन्य को इस जांच के तहत गिरफ्तार किया था।

कब हुआ था कथित घोटाला?

छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला साल 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जब यहां सीएम बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। इस जांच के तहत अब तक एजेंसी द्वारा विभिन्न आरोपियों की लगभग 205 करोड़ रु पये की संपत्ति कुर्क की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस मामले में ईडी की पहली ईसीआईआर (एफआईआर) को खारिज कर दिया था जो आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित थी। संघीय एजेंसी ने बाद में एक नया मामला दर्ज किया, जब उसने छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू/एसीबी को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा साझा की गई सामग्री के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा।

शराब घोटाला साल 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जब यहां सीएम बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। इस जांच के तहत अब तक एजेंसी द्वारा विभिन्न आरोपियों की लगभग 205 करोड़ रु पये की संपत्ति कुर्क की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस मामले में ईडी की पहली ईसीआईआर (एफआईआर) को खारिज कर दिया था जो आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित थी।

ईओडब्ल्यू/एसीबी ने पिछले साल 17 जनवरी को एफआईआर दर्ज की थी, विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा मौजूदा कांग्रेस सरकार को हराने के लगभग एक महीने बाद, और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांड और अन्य सहित 70 व्यक्तियों और कंपनियों को नामजद किया था। ईडी के मुताबिक, शराब की अवैध बिक्री से अर्जित कमीशन को राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारियों के इशारों पर बांटा गया था।

छत्तीसगढ़ का कोयला घोटाला: एक नजर में

जांच एजेंसी ने 2022 में आरोप लगाया था कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य में कोयला-लेवी घोटाला करने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें पिछले दो वर्षों में कुल 540 करोड़ की उगाही की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आयकर विभाग द्वारा दर्ज की गई शिकायत से उपजा है। ईडी की जांच एक बड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों की मिलीभगत से छत्तीसगढ़ में परिवहन किए जाने वाले प्रत्येक टन कोयले पर 25 रु पये की अवैध उगाही की जा रही थी', एजेंसी ने दावा किया था। जब यह घोटाला हुआ उस

समय प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार थी।

कोयला घोटाले में कई अधिकारी जेल में

छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी घोटाले को लेकर राज्य के कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। इस मामले में कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि वह इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है। ईडी की टीम कोयला घोटाला और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है। भूपेश बघेल सहित कुल 14 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के यहां भी ईडी की टीम पहुंची थी। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। सौम्या राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वह सबसे पावरफुल लेडी अधिकारी मानी जाती थीं। वह सीएम ऑफिस में पदस्थ थीं।

पत्रकारों पर अत्याचार

भूपेश सरकार में प्रदेश के पत्रकारों पर काफी अत्याचार हुए थे। जो भी पत्रकार भूपेश सरकार के विरोध में लिखता था उसकी सामत आ जाती थी। यही वजह रही कि कई पत्रकारों पर झूठे केस लांधकर जेलों में डाला गया। जेल में भी उन्हें कई तरह की यातनाएं दी गई। कोई एक दर्जन पत्रकारों पर झूठे केस लादे गये। पत्रकारों को इतना प्रताड़ित किया जाता था कि वह दर-दर की ठोकरे खाने मजबूर होते थे।

Ambedkar's insights and foresight remain deeply underappreciated

Sudhir Hilsayan

In 2025, India stands at a historic crossroads, commemorating two monumental milestones: the 134th birth anniversary of Dr B.R. Ambedkar and the 75th anniversary of the Constitution coming into force. This is a profound juncture to reflect on the nation's democratic journey, its unfulfilled promises, and the enduring relevance of Ambedkar's radical vision. Born into the stigmatised Mahar caste in 1891, Ambedkar emerged as a colossus of modern India a jurist, economist, feminist, and the principal architect of a Constitution that sought to dismantle centuries of caste tyranny. As India celebrates its 75 years of constitutional governance, his warnings about the "life of contradictions" between political equality and socio-economic inequality echo with unsettling urgency.

It is now 75 years since India's Constitution came into force on 26 January 1950, a document Ambedkar described as a "social contract" to redeem the nation from the "grammar of caste". Its adoption was revolutionary: a post-colonial democracy granting universal adult suffrage from its inception, either enshrining or allowing for affirmative action for the historically oppressed communities (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes). Yet, Ambedkar's closing speech to the Constituent Assembly in 1949 struck a cautionary note: "We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy."

Dr Ambedkar's 134th birth anniversary is a call to confront these contradictions. His life a saga of battling caste apartheid, drafting the Constitution, and ultimately renouncing Hinduism to embrace Buddhism embodies the struggle to reconcile legal equality with social equity. As the architect of India's affirmative action framework, he recognized that formal equality was insufficient to dismantle caste's "graded hierarchy". His vision demanded substantive equality redistribution of land, education and political power to Dalitbahujan communities. Today, as India debates caste-based censuses and wrestles with the

intersection of technology and inequality, Dr Ambedkar's ideas offer a roadmap to bridge the constitutional promise with ground realities.

In this context, while Dr Ambedkar is celebrated as the Constitution's chief draftsman, his legacy transcends this role. He was a polymath whose contributions spanned economics, gender justice, and philosophy. As an economist, he critiqued Brahmanical capitalism in *The Problem of the Rupee* (*1923*) and advocated for land reforms to dismantle feudal structures. As a feminist, he drafted the Hindu Code Bill in the 1950s to grant women property rights and divorce protections a bill so radical that it triggered a backlash from conservative MPs, leading to his resignation as law minister. Though the bill was diluted, its principles later shaped progressive laws like the Hindu Succession (Amendment) Act (2005). His magnum opus, *Annihilation of Caste* (*1936*), remains a blistering indictment of Hinduism's caste system, arguing that "applying the dynamite" to the religious texts that sanction it was a prerequisite to political democracy.

In the global context, Dr Ambedkar's ideas resonate with movements for racial justice, intersectional equity, and human rights. His correspondence with W.E.B. Du Bois in the 1940s revealed a shared vision for dismantling systemic oppression, with Dalitbahujan activists today drawing parallels between caste apartheid and anti-Black racism. Yet, Western academia often marginalizes Ambedkar, favouring Eurocentric thinkers like John Locke or Rousseau.

Ambedkar as democracy's unsung hero

Dr B.R. Ambedkar's vision of democracy transcended the simplistic notion of majority rule. He critiqued majoritarian democracy as a system that risked perpetuating the tyranny of dominant groups over marginalized communities. For Dr Ambedkar, democracy was not merely procedural it demanded substantive equality, where historically oppressed castes, women, and religious minorities

could live with dignity and could access resources and power. Unlike formal equality, which treats all citizens identically regardless of systemic disadvantages, substantive equality requires proactive measures to compensate for historical injustices. This principle underpinned his advocacy for reservations (affirmative action) and land redistribution.

Central to his democratic philosophy was constitutional morality the idea that constitutional values must permeate societal consciousness, not just exist as legal texts. He warned against reducing democracy to elections, emphasizing, instead, cultivation of ethics like fraternity, accountability, and respect for dissent. His insistence on minority rights stemmed from his lived experience of caste apartheid; he argued that democracy's strength lay in protecting the weakest, not empowering the majority. This vision of social democracy a fusion of political rights with economic and social justice challenged India to move beyond symbolic freedoms. “Democracy is not merely a form of government,” he asserted, “It is primarily a mode of associated living.” As Chairman of the Drafting Committee, Dr B.R. Ambedkar embedded his democratic ideals into India's constitutional DNA.

1. Fundamental Rights: Articles 14-18 guarantee equality before the law, prohibit discrimination, and abolish untouchability (Article 17), directly targeting caste hierarchy.

2. Directive Principles: These non-justiciable guidelines (Articles 36-51) prioritize social welfare, workers' rights, and equitable resource distribution, balancing individual liberty with collective welfare.

3. Affirmative Action: Articles 15(4) (after the first amendment in 1951) and 16(4) enabled reservations for Scheduled Castes, Scheduled

Tribes and Other Backward Classes, operationalizing his belief that historical oppression demanded reparative justice.

Dr Ambedkar's genius lay in reconciling competing imperatives. He defended free speech (Article 19) while allowing reasonable restrictions to prevent communal harm. He championed federalism but advocated for a strong centre to unify a fragmented post-colonial society. His defence of the Hindu Code Bill aimed at granting women property rights and outlawing polygamy highlighted his commitment to gender justice, even amid fierce opposition. However, he cautioned that constitutional rights alone were insufficient: "However good a Constitution may be, if those implementing it are not good, it will prove to be bad."

Despite the many constraints he faced, Dr Ambedkar's legal expertise, intellectual acumen, and commitment to democracy allowed him to steer the Drafting Committee toward embedding fundamental values into the Constitution. Under his leadership, the document enshrined ideals such as Liberty, Equality, and Fraternity, a comprehensive framework for Fundamental Rights and Directive Principles, a federal structure with a clear separation of powers, an independent judiciary, and crucial affirmative action policies like reservations.

The Indian Constitution, born from these efforts, became more than just a legal framework it emerged as the most powerful tool for the Indian people in their fight against oppression, discrimination, and injustice, ensuring that the democratic spirit of the nation remained alive and resilient.

Yet, Dr Ambedkar remains under-recognized in Western and Indian academia, overshadowed by Eurocentric narratives of liberty. His critique of majoritarianism and advocacy for minority rights offer urgent lessons, as democracies worldwide grapple with polarization. In this age of rising authoritarianism, Dr Ambedkar's insistence on constitutional morality not just as law, but as a collective ethic positions him as a global democratic visionary.

Way forward

As India marks the 134th birth anniversary of Dr Ambedkar, it serves as a reminder to re-examine democratic values, inclusivity, and social justice. His principles continue to guide government policies, from educational and economic reforms to social welfare and legal protections. The need of the hour is to mobilize Dr Ambedkar's ideas to address modern global challenges. Climate justice, ethical AI governance, and reducing global inequalities are areas where his philosophy of social justice can be applied. By integrating his ideals with contemporary governance models, India can lead the world in fostering a just, inclusive, and progressive society.

दृढ़ता से आगे बढ़ती
मध्यप्रदेश की
जल संरक्षण यात्रा
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
जल गंगा संवर्धन अभियान
30 मार्च से 30 जून, 2025
जल गंगा
"प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जल संरक्षण अभियान से प्रेरित मध्यप्रदेश में सरकार और समाज की साझेदारी से वर्षा जल की बूंद-बूंद बचाने का "जल गंगा संवर्धन" अभियान प्रारंभ हुआ है। जन, जल, जंगल, जमीन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संकल्पित मध्यप्रदेश का यह अभियान जन आंदोलन बन रहा है।"
- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
• लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बनाये जायेंगे 50 हजार खेत-तालाब
• 90 दिनों में 90 लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का होगा लोकार्पण
• ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व वाले जल स्रोतों एवं देवालयों की सफाई के साथ होगा जीर्णोद्धार
• 1000 नए तालाबों का निर्माण एवं 50 से अधिक नदियों के वॉटर शेड क्षेत्र में जल संरक्षण एवं संवर्धन के होंगे कार्य
• अनुपयोगी तालाब, चेक डैम एवं स्टॉप डैम का जीर्णोद्धार एवं हर दिन एक जल संरचना का होगा लोकार्पण
• नर्मदा परिक्रमा पथ का चिन्हांकन कर जल संरक्षण एवं पौधरोपण की योजना
• ग्रामीण क्षेत्रों में पानी चौपाल का आयोजन, प्रत्येक गांव से महिला-पुरुषों का चयन कर तैयार किए जाएंगे 1 लाख जलदूत
• सीवेज का गंदा पानी जल स्रोतों में न मिले, इसके लिए सोक पिट निर्माण को प्रोत्साहन
• 54 जल संरचनाओं का संवर्धन एवं नहरों को विलेज-मेप पर "शासकीय नहर" के रूप में किया जाएगा अंकित
• बांध तथा नहरें होंगी अतिक्रमण मुक्त, करीब 40 हजार किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली की होगी साफ-सफाई
• सदानीरा फिल्म समारोह, जल सम्मेलन, प्रदेश की जल परंपराओं पर आख्यान, चित्र प्रदर्शनी समेत विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे आयोजित
आइये, मिलकर सहेजें अपने जल स्रोतों को
जल दूत के रूप में सहभागिता के लिए
mybharat.gov.in
पर पंजीयन करायें
RO.No. D19080/25
मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भूमि विवाद का तकनीकी समाधान
जिओ रिफ्रेंसिंग
छोटी से छोटी भूमि का अक्षांश और देशांतर के माध्यम से वास्तविक भूमि चिन्हांकित करना आसान
भूमि के नक्शों के लिए खसरा के स्थान पर यू.एल.पिन नंबर
RO. No. 13282/1
सुशासन से समृद्धि की ओर
Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

छत्तीसगढ़ शासन
औद्योगिक नीति
अब और अधिक रोजगारपरक, व्यापक
और उद्यमों के लिए लाभकारी
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष अनुदान
आधुनिक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को मिलेगा बढ़ावा
वस्त्र क्षेत्र में निवेश पर अब 200 फीसदी तक का प्रोत्साहन
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर को विशेष पैकेज
पर्यटन और होटल व्यवसाय को बढ़ावा
नीति में संशोधन से युवाओं, किसानों, उद्यमियों और निवेशकों को सीधा लाभ
RO. No. 13282/1
QR स्कैन करें
विष्णु के सुशासन से संवर रहा छत्तीसगढ़
Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क